उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विज्ञापन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

बी पी एस न्यूज

सच का साथी.....

www.bpsnews.in

वर्षः 11 || अंकः 24 || पृष्ठः 8 || मूल्य 2:00/- रुपए || कानपुर || सोमवार || 13 जुलाई-2026

अंदर के पृष्ठ पर

कानपुर कचहरी में वकील-कांस्टेबल में हुई सरेआम जमकर मारपीट 4

कहां गई कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा? केरल हाईकोर्ट ने रद्द की पुलिस सुरक्षा 5

गोरखपुर से सीएम योगी ने शुरू किया एक पेड़ मां के नाम अभियान, दोपहर 2 बजे तक लगे 22 करोड़ पौधे

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित

» बीपीएस न्यूज

गोरखपुर। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाना और लोगों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। उन्होंने कहा कि बढ़ते जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच अधिक से अधिक पौधारोपण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रविवार को एक पेड़ मां के नाम थीम पर आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ पूरे उत्साह के साथ जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से अभियान का शुभारंभ किया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दोपहर 2 बजे तक प्रदेशभर में 22 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य शाम 6 बजे तक 35 करोड़ पौधे लगाने का है। अभियान में वन विभाग, विभिन्न सरकारी विभागों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यालयों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है।

धरती माता के प्रति कृतज्ञता का महायज्ञ-सीएम योगी

गोरखपुर में अभियान की शुरुआत करते हुए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम केवल पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महायज्ञ है। उन्होंने कहा कि धरती माता हमें अन्न, जल, फल और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य और संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम सभी की है।प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ा अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाना और लोगों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। उन्होंने कहा कि बढ़ते जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच अधिक से अधिक पौधारोपण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश सरकार के अनुसार, सभी जिलों में युद्धस्तर पर पौधारोपण अभियान चल रहा है। प्रशासन को शाम 6 बजे तक 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।लखनऊ में चला वृक्षारोपण अभियान, लोगों ने बढ़-चढ़कर किया पौधारोपण

लखनऊ- गोमती नगर स्थित देव पार्क में रविवार को सनातन समिति उत्तर प्रदेश, हास्य देव-वन समूह, कर्तव्य पथ वेल्फेयर सोसाइटी विनीत खंड तथा स्थानीय नागरिकों के संयुक्त तत्वावधान में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से जामुन, सहजन, कड़ी पत्ता, बॉटल ब्रश, पीपल, गूलर और पाकड़ समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जनार्दन के नाम्बियार, एस.एन. शुक्ला, बलराम मिश्रा, ए.के. उपाध्याय, नरेंद्र चौधरी, दिलीप कुमार सक्सेना, आर.एस. नेगी, जयराम सिंह राठौड़, रवि शुक्ला, सुनील महरोत्रा, जगदीश दुबे, सत्य प्रकाश त्रिपाठी सहित कई गणमान्य लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्र पति, प्रधानमंत्री गृहमंत्री ने पार्श्व गायिका जानकी अम्मा के निधन पर शोक जताया

» बीपीएस न्यूज

दिल्ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर शोक प्रगट किया है। इनका कहना है कि जानकी अम्मा के निधन से संगीत ने एक महान हस्ती को खो दिया है, जिनकी असाधारण गायकी ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया।दक्षिण भारत की कोकिला के नाम से मशहूर एस. जानकी का 88 वर्ष की आयु में शनिवार को मैसूरु में वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। उनका 20 से अधिक भाषाओं में 48 हजार से अधिक गीतों के साथ छह दशक का करियर रहा है। एस. जानकी ने हिंदी सिनेमा में कई सदाबहार गीत गाए हैं। उनके लोकप्रिय गीतों में बप्पी लाहिड़ी के साथ यार बिना चैन कहां रे, गोरी का साजन, साजन की गोरी, सुन रुबिया और घायल घायल तूने मुझे कर दिया शामिल हैं। नैनो में निंदिया है और हसीनों का दस्तूर भी उनके चुनिंदा हिंदी गानों में से हैं।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनका कालातीत संगीत हमेशा अनमोल रहेगा। उनके निधन से भारत ने एक संगीत की महान हस्ती को खो दिया है। उनकी असाधारण गायकी ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया। उनका गौरवशाली करियर छह दशकों से अधिक समय तक फैला रहा, जिसके दौरान उन्होंने हिंदी, ओडिया, तुलु, उर्दू, पंजाबी और बंगाली सहित लगभग 20 भारतीय भाषाओं में हजारों गीत रिकॉर्ड किए।उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनन ने जानकी अम्मा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी असाधारण आवाज ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया और पीढ़ियों से अनगिनत दिलों को छुआ। उनके गीतों ने भाषाई और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हुए संगीत की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से लाखों लोगों को एकजुट किया।

अमित शाह ने अहमदाबाद में 405 करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास

» बीपीएस न्यूज

अहमदाबाद। शहर को हराभरा और प्रदूषणमुक्त बनाने के उद्देश्य से अहमदाबाद महानगरपालिका द्वारा 'मिशन फाइव मिलियन ट्री' के तहत भव्य सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार को साइंस सिटी के विज्ञान भवन में आयोजित मेगा कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 405 करोड़ की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

'मिशन फाइव मिलियन ट्री' परियोजना के तहत शहर में हरित विकास को बढ़ावा देने वाले हेरिटेज पार्क और 101 ऑक्सीजन पार्क-अर्बन फॉरेस्ट का भी अमित शाह ने लोकार्पण किया। ग्रीन मोबिलिटी के तहत बीआरटीएस नेटवर्क में 80 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई। इसके साथ ही एएमटीएस के बेड़े में भी 75 नई एसी बसें शामिल की गईं।

कार्यक्रम के दौरान 60.68 करोड़ की लागत से निर्मित 188 आधुनिक सरकारी आवासों का भी ई-लोकार्पण किया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने भाड़ज, बोपल और वाडज सहित विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया।

इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि आज मैं अहमदाबाद शहर और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को हृदय से नमन और अभिनंदन करता हूं। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आज एक ही दिन में नागरिकों ने मिलकर 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पौधे लगाने का भगीरथ कार्य किया है,

जबकि अहमदाबाद शहर की तीनों लोकसभा सीटों में अलग से 50 लाख पौधे लगाने का महाअभियान चलाया गया है।उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले जब उन्होंने बैठक में यह विचार रखा था, तब किसी ने स्पष्ट रूप से हां या ना नहीं कहा था, लेकिन आज जनता ने इसे साकार कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का आह्वान किया है, ताकि लोग अपनी मां और धरती माता की स्मृति में एक-एक पौधा लगाएं।अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने सात वर्षों में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा आज अत्यंत आवश्यक हो गई है। वाहनों के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए शहरों में हरियाली बढ़ाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

उन्होंने कहा कि गांधीनगर क्षेत्र में पहले केवल 12 पार्क थे, जबकि अब 61 नए ऑक्सीजन पार्कों का लोकार्पण किया गया है। पूरे अहमदाबाद में अहमदाबाद महानगरपालिका द्वारा 101 ऑक्सीजन पार्क विकसित किए गए हैं। इस आयोजन के लिए उन्होंने अहमदाबाद महानगरपालिका और मेयर हितेश बारोट को बधाई दी। उन्होंने बताया कि महानगरपालिका ने नागरिकों के घरों तक पौधे पहुंचाने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था भी की है।अमित शाह ने कहा, मैंने वर्ष 2029 के चुनाव तक इस क्षेत्र में 20 प्रतिशत हरियाली बढ़ाने का व्यक्तिगत संकल्प लिया है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ गांधीनगर क्षेत्र ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी अग्रणी है। देश में सबसे अधिक सोलर रूफटॉप वाले क्षेत्रों में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र प्रमुख है। प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से नई इलेक्ट्रिक बसों को भी सेवा में शामिल किया गया है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।

अमित शाह ने बताया कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक कुल 1,25,93,513 पौधे लगाने का कार्य पूरा होने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में अब तक कुल 28,492 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

अंत में उन्होंने नागरिकों से दो विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी सोसायटी का कोई कोना पेड़ के बिना खाली न रहे और अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को रहने योग्य बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों से अपने घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने का आह्वान करते हुए कहा, इए, हम सब मिलकर अपने क्षेत्र को ग्रीन और क्लीन बनाएं।

सोलर लगाने के लिए पैसे की चिंता होगी खत्म, वर्ल्ड बैंक देगा 4.2 अरब डॉलर की मदद

नयी दिल्ली। अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो आने वाले समय में यह पहले से ज्यादा आसान हो सकता है। विश्व बैंक ने भारत के रूफटॉप सोलर मिशन के लिए बड़े वित्तीय पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत लाखों परिवारों को आसान शर्तों पर कर्ज मिलेगा, ताकि वे अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का खर्च कम कर सकें।

विश्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वह निजी क्षेत्र के जरिए 4.2 अरब डॉलर (करीब 36 हजार करोड़ रुपये) का कर्ज उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह पैसा बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के जरिए लोगों तक पहुंचेगा, ताकि वे बिना ज्यादा परेशानी के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकें।यह फंडिंग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए दी जा रही है। सरकार ने यह योजना फरवरी 2024 में शुरू की थी। इसका मकसद देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाना है। अब तक इस योजना के तहत 40 लाख से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं।विश्व बैंक के इस पैकेज में 820 मिलियन डॉलर का कर्ज, 60 मिलियन डॉलर का रियायती लोन और 10 मिलियन डॉलर की ग्रांट भी शामिल है। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को कर्ज देने में ही नहीं।

बिना मोबाइल नेटवर्क के भी होगी बात

बीएसएनएल ने लॉन्च किया सैटेलाइट फोन

नयी दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक बेहद खास सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। यह फोन उन सुदूर इलाकों में भी वॉयस कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा देगा, जहां आम मोबाइल नेटवर्क की पहुंच बिल्कुल नहीं होती है। टैक्स मिलाकर इस हैंडसेट की कुल कीमत 1,34,166 रुपये रखी गई है। इसे खास तौर पर पहाड़ों, घने जंगलों और मुश्किल रास्तों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां न तो मोबाइल टावर होते हैं और न ही सामान्य नेटवर्क काम करते हैं। आम स्मार्टफोन से अलग, यह फोन नजदीकी सेल्युलर टावर के बजाय सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से कनेक्ट करता है। आम मोबाइल फोन कॉल करने या इंटरनेट चलाने के लिए आसपास लगे मोबाइल टावर पर निर्भर होता है। लेकिन बीएसएनएल का यह सैटेलाइट फोन सीधे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। यही वजह है कि यह समुद्र के बीच, ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तान, माइनिंग एरिया और सीमावर्ती इलाकों जैसी दूर-दराज की जगहों पर भी भरोसेमंद तरीके से काम करता है।

इतना ही नहीं, बाढ़, भूकंप या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं, तब यह फोन इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही यह सुरक्षा व राहत टीमों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। बीएसएनएल ने इस हैंडसेट को इनमारसैट जैसे ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर तैयार किया है।

अमरनाथ धाम के लिए 11वें जत्थे में 9,153 से ज्यादा तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना

» बीपीएस न्यूज

जम्मू। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच 9,153 तीर्थयात्रियों का 11 वां जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ।

सुरक्षा कर्मियों और सिविल प्रशासन ने जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तीर्थयात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की। उनकी सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, ट्रैफ़िक कंट्रोल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए व्यापक इंतज़ाम किए गए थे।अधिकारियों ने बताया कि इस नए जत्थे में 2,345 महिलाएं और 18 बच्चे हैं। तीर्थयात्रियों का 11वां जत्था 359 गाड़ियों में सवार होकर कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था के तहत दो अलग-अलग काफिलों में बेस कैंप से निकला। पहले काफिले में 3,429 तीर्थयात्री थे, जो सुबह 2:44 बजे गांदरबल ज़िले के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए। दूसरे काफिले में 5,724 तीर्थयात्री थे, जो सुबह 3:35 बजे अनंतनाग ज़िले के नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप के लिए निकले।अधिकारियों के अनुसार इस साल तीर्थयात्रा में लोगों की भारी भागीदारी देखी गई है।

3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से 2.30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के अंदर प्राकृतिक रूप से बने बर्फ़ के शिवलिंग के दर्शन और पूजा-अर्चना की है।

7 दिनों तक चलने वाली यह सालाना तीर्थयात्रा 28 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले हफ़्तों में भी तीर्थयात्रियों का आना जारी रहेगा।

पुणे के मोशी हादसे में 9 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों को 40 लाख रुपये की आर्थिक मदद

» बीपीएस न्यूज

मुंबई। पुणे जिले के मोशी इलाके में तीन मंजिला बिल्डिंग गिर जाने से हुए हादसे में 83 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन रविवार को पूरा हो गया है। आज सुबह तक नौ कर्मचारियों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल में भेज दिए गए हैं। हादसे में कुल 9 लोगों को बचा लिया गया है। इस घटना में मृतक कर्मचारियों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 40 लाख रुपये की मदद घोषित की गई है।

पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में 8 जुलाई को करीब दो बजे जमा किए गए कचरे के ढेर के पास तीन मंजिला एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ढह गई थी। हादसे के समय बिल्डिंग में कुल 23 कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन हादसे की भनक लगते ही पांच कर्मचारी भाग कर बिल्डिंग से निकल गए थे, जबकि 18 कर्मचारी घटनास्थल पर बिल्डिंग के मलबे में अटक गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर पिंपरी नगर निगम की टीम, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (एनडीआरएफ), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की टीम, भारतीय सेना की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर करीब 83 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रविवार को सुबह

तक नौ कर्मचारियों के शव बाहर निकाले गए। इस दौरान कुल नौ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इनमें से सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम के आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने रविवार को मीडिया को बताया कि घटनास्थल पर करीब 83 घंटे बाद तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार आज सुबह पूरा हो गया है और इस हादसे में नौ कर्मचारियों की मौत हुई है। यह ऑपरेशन बड़ी मात्रा में मशीनरी, डॉग स्क्वॉड, लाइव डिटेक्टर, साउंड डिटेक्टर के साथ-साथ पोकलेन और डंपर की मदद से पूरा किया गया है। मौके पर फंसे कर्मचारियों को ढूंढने के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग के कंक्रीट वाले हिस्से को तोडक़र अंदर पहुंचने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया।

उन्होंने बताया कि पूरे ऑपरेशन में करीब 90 लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि, सभी लापता लोगों को जिंदा बाहर निकालने की कोशिशें आखिरकार नाकाम रहीं। इस हादसे में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है और इलाके में दुख फैल गया है।

मुंबई नगर निगम की टीम की पूरी संवेदना मृतक परिवारों के साथ हैं। आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उस कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मृत कर्मचारियों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 40 लाख रुपये की मदद घोषित की गई है। इनमें प्रत्येक 5 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से, 25 लाख रुपये वेस्ट-टू-एनर्जी कंपनी की ओर से और 10 लाख रुपये पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम की ओर से घोषित की गई है।

अमेरिका का बड़ा सैन्य अभियान, ईरान के करीब 140 ठिकानों पर हवाई हमले; जवाबी कार्रवाई में ईरान ने खाड़ी देशों को बनाया निशाना

» मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को बनाया निशाना

» ईरान ने किया जवाबी हमला

» बीपीएस न्यूज

दुबई। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने रविवार को कहा कि उसने ईरान के करीब 140 ठिकानों पर हवाई हमले कर अपने हालिया सैन्य अभियान का यह चरण पूरा कर लिया है। अमेरिकी सेना के अनुसार, इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उन क्षमताओं को कमजोर करना था, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले असैन्य जहाजों और वाणिज्यिक नौवहन को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है।अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों के दौरान मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थल, गोला-बारूद के भंडार, संचार उपकरण और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया।सेंटकॉम के अनुसार, यह कार्रवाई क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।

अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने रविवार सुबह जवाबी कदम उठाते हुए बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को निशाना बनाकर हमले किए। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन हमलों से हुए नुकसान या हताहतों का कोई आधिकारिक विवरण नहीं दिया गया है।अमेरिका और ईरान के बीच इस ताजा सैन्य कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है ।

अपनी बात....

संपादकीय .....

ज़्यादा अल्कोहल वाली दवाओं का नियमन सराहनीय

सार्वजनिक विमर्श में लंबे समय से मांग की जाती रही है कि ज्यादा अल्कोहल की मात्रा वाली दवाओं का सख्ती से नियमन किया जाए। दरअसल, नशे की लत छुड़ाने के प्रयासों के दौरान इन दवाओं का दुरुपयोग किया जाता रहा है। साथ ही जिन राज्यों में नशाबंदी लागू है, वहां भी उनके गलत इस्तेमाल की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का ज्यादा अल्कोहल की मात्रा वाली पीने वाली दवाइयों व सिरप की बिक्री पर सख्ती करने का फैसला, एक जरूरी सुधार है। निश्चय ही इस कदम से लंबे समय से इन दवाइयों के गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी। दरअसल, 12 प्रतिशत से ज्यादा एथिल अल्कोहल मात्रा के साथ बड़ी बोतल में मिलने वाली दवाइयों के लिये अब लाइसेंस, डॉक्टर की पर्ची और रिकॉर्ड रखने के नियम कड़े करके सरकार ने जरूरी पहल की है। आखिरकार सरकार ने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, जिसे रेगुलेटर लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। यह हकीकत है कि इन दवाओं का नियमन व निगरानी कायदे की न होने से ये दवाएं नशा करने का जरिया भी बन रही थीं। निश्चित रूप से ये नये नियम मरीजों की दवा तक पहुंच और जन-सुरक्षा के बीच समझदारी भरा संतुलन बनाते हैं।

इसका मतलब ये है कि जिन्हें वास्तव में इन दवाइयों की जरूरत है, उन्हें ये दवाइयां डॉक्टर की देखरेख में सहज उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं दूसरी ओर इन दवाइयों का दुरुपयोग गलत कार्य के लिये करने वालों की इन तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी। निश्चय ही यह वक्त की जरूरत थी क्योंकि किशोर और नशे की लत से जूझ रहे लोग अक्सर ऐसी दवाइयों को शराब के सस्ते विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। जनमानस में उपचार के लिये आम बोलचाल में प्रचलित शब्द 'दवा-दारू', वास्तव में ऐसे नशेड़ियों के लिये नशे का मौका उपलब्ध कराने का जरिया बन जाता था। इस पर अंकुश लगाना निश्चिय ही स्वागत योग्य कदम है।

दरअसल, एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ने नशीले पदार्थों की लत छुड़ाने के लिये इलाज करा रहे लोगों के बीच इन दवाइयों व कफ सिरफ आदि के अनुचित इस्तेमाल का पर्याप्त रिकॉर्ड रखा है। इतना ही नहीं, जन स्वास्थ्य से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस बाबत चिंता जाहिर कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो बाकायदा चेतावनी दी है कि जिन जगहों पर सामान्य शराब महंगी होती है या नशाबंदी लागू होने से आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, वहां अधिक अल्कोहल वाली दवाइयों के दुरुपयोग की लगातार संभावना बनी रहती है। जो इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि जैसे-जैसे नशीले पदार्थों के रूप में दवाइयों का दुरुपयोग बढ़ता है, वैसे-वैसे ही नियमों में बदलाव करना अपरिहार्य हो जाता है। बहरहाल, कागजों पर नियम बना देना तो मात्र एक शुरुआत भर है। सबसे जरूरी है कि इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही निगरानी तंत्र को भी मजबूत बनाने की जरूरत है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि नियमों को तोड़कर दवा के दुरुपयोग की कोशिश करने वालों की निगरानी के लिये ड्रग इंस्पेक्टरों की पर्याप्त संख्या हो। इसके अलावा फार्मेसियों को भी इस बाबत जवाबदेह बनाना जरूरी हो जाता है। जिसके लिये ऐसी दवाइयों की बिक्री के रिकॉर्ड को डिजिटल करना भी आवश्यक है ताकि नियामक तंत्र इनकी बिक्री की निगरानी कर सके।

निस्संदेह, डॉक्टरों का भी नैतिक दायित्व है कि वे जरूरतमंद लोगों को ये दवाइयां सोच-समझकर ही लिखें। साथ ही इससे होने वाले खतरों के बारे में भी मरीजों को अवगत कराएं। इन बोतलों पर दवा का लेबल लगाने का अंतिम निष्कर्ष यह नहीं है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बहरहाल, नियमों में बदलाव सरकार की एक बुनियादी जिम्मेदारी को ही दर्शाता है। जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि इलाज के लिए उपयोग होने वाले उत्पादों से लोगों को फायदा ही हो, नुकसान नहीं। निस्संदेह, सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है। अब इस नियम को सख्ती से लागू करने का पक्का इरादा भी दिखाना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस रोग का पूरा इलाज नहीं हो पायेगा।

दरअसल, 12 प्रतिशत से ज्यादा एथिल अल्कोहल मात्रा के साथ बड़ी बोतल में मिलने वाली दवाइयों के लिये अब लाइसेंस, डॉक्टर की पर्ची और रिकॉर्ड रखने के नियम कड़े करके सरकार ने जरूरी पहल की है। आखिरकार सरकार ने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, जिसे रेगुलेटर लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। यह हकीकत है कि इन दवाओं का नियमन व निगरानी कायदे की न होने से ये दवाएं नशा करने का जरिया भी बन रही थीं।

भरोसे के संकट को दूर करने की जरूरत

निरंजन भंडारी

अगर थोड़ा-सा विश्वास वरिष्ठ शिक्षक जनों पर करके परीक्षा प्रणाली को उनके हवाले कर दिया जाता तो शिक्षक अपने पेशे के प्रति ईमानदार होते हुए अपनी अंतरात्मा का हनन कभी नहीं करेंगे।

सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में ज्ञानार्जन की समस्या है, पुस्तक संस्कृति के घटते जाने की समस्या है। हमने 2024 में नीट की परीक्षा आयोजित की। नकल और अवैध तरीकों के इस्तेमाल के कारण परीक्षा की शुद्ध ?ता बुरी तरह से प्रभावित हुई और लाखों छात्रों को पुन- परीक्षा देनी पड़ी। यदि इस अनुभव से सबक लेते तो इस बार दोबारा परीक्षाएं आयोजित न करनी पड़ती। लेकिन 2026 में जब फिर नीट परीक्षा आयोजित हुई तो फिर पेपर लीक का मामला उजागर हुआ। इस घटनाक्रम ने देश की पठन-पाठन, शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन की शुचिता के बारे में बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। भारत के युवाओं का भविष्य सटीक ज्ञान के बगैर अधूरा है और चोर गलियों से सफलता के प्रतिमान स्थापित नहीं किए जा सकते।

देश में नीट की परीक्षा दूसरी बार जिस तरह आयोजित हुई, जिनकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई। प्रश्न पत्रों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल, टेलीग्राम एप को बंद कर देने जैसे उपाय छात्रों को त्रिस्तरीय जांच के बाद ही परीक्षा केन्द्रों में भेजा गया। बायोमीट्रिक जांच हुई, फिजिकल जांच हुई, दूसरे दस्तावेज जांचे गए। सात लाख सुरक्षा कर्मी और पर्यवेक्षक तैनात रहे। हर परीक्षा कक्ष में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया।

करीब 1.38 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों से 95 हजार कक्षों पर नजर रखी गई और छात्र जाम में न फंसें, इसलिए प्रधानमंत्री भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 45 मिनट रुके रहे। इसके बावजूद बिहार में 9 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए । जिनमें 7 मेडिकल के छात्र थे। सबसे पहले जब पहली बार परीक्षा हुई तो 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, इस बार दोबारा परीक्षा हुई तो 20 लाख छात्र परीक्षा देने बैठे। पहला सवाल यही है कि दो लाख से अधिक छात्र दोबारा क्यों नहीं बैठे? चाहे रिपोर्ट कहती है कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और कहीं गड़बड़ी की सूचना नहीं है। लेकिन गड़बड़ी तो पहले ही पैदा हो गई थी जब पहली परीक्षा के बाद दोबारा परीक्षा की घोषणा से पूरे देश में अवसादग्रस्त होकर कई युवा छात्रों ने आत्महत्या कर ली।

केन्द्र सरकार के दर्जनों मंत्रालयों के साथ राज्य सरकारों व एजेंसियों ने 37 दिनों तक एकजुट होकर काम किया। यह सही है कि परीक्षाएं पूरी तरह से सफल रहने की घोषणाएं की जा रही हैं लेकिन असल में ये कितनी सफल हुई हैं इसका पता तो परिणामों की घोषणा के साथ ही चलेगा।

शिक्षाविदों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अचानक इतने वर्षों के बाद परीक्षा व्यवस्था इतनी भयावह समस्या क्यों बन गई कि इसके आयोजन के लिए वायुसेना से लेकर लाखों पुलिसकर्मियों की मदद लेनी पड़ी; और इसके बावजूद बड़े पैमाने पर नकल करते हुए छात्र पकड़े जा रहे हैं। क्या इस स्थिति का मूल कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रति पैदा हुआ अविश्वास है?

आज कुछ संस्थाएं परीक्षा की ठेकेदारी कर रही थीं, उन्हीं पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पेपर लीक किए हैं। क्यों विद्यार्थियों पर इतना अविश्वास किया गया कि उनके परीक्षा केन्द्र बदलकर उन्हें दूर-दूर तक परीक्षा देने जाना पड़ा। जैसे पहले के वर्षों में चलता रहा है क्या उसी तरह से परीक्षाएं उन्हीं केन्द्रों में नहीं करवाई जा सकती थीं, जहां से छात्र संबंध रखते थे।अगर थोड़ा-सा विश्वास वरिष्ठ शिक्षक जनों पर करके परीक्षा प्रणाली को उनके हवाले कर दिया जाता तो शिक्षक अपने पेशे के प्रति ईमानदार होते हुए अपनी अंतरात्मा का हनन कभी नहीं करेंगे अभी भी 90 प्रतिशत शिक्षक ऐसे ही हैं। उन मासूम छात्रों के बारे में सोचा जाए जिन्होंने दिन-रात एक करके पूरी मेहनत से परीक्षाएं दीं लेकिन अचानक उन्हें यह संदेश दिया गया कि पिछली मेहनत व्यर्थ है, अब दोबारा परीक्षा दो। हम समझते हैं कि इस समस्या का समाधान यही है कि परीक्षा लेने वालों और परीक्षा देने वालों पर पूरा विश्वास किया जाए। उनके लिए सुविधाजनक केंद्र बनाए जाएं। तब असामाजिक तत्व सारा तंत्र बिगड़ने पर आमादा हो जाएं तो उन्हें चुनकर बाहर फेंकना आसान हो जाएगा।

इस समय परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। यह नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, पूरी मेहनत और शिक्षण और शिक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण के बिना नहीं हो सकता। अपराधी तलाश करने की जगह छात्रों की मेहनत और अध्यापकों के नैतिक कर्तव्य पर विश्वास को प्राथमिकता दी जाए तो परीक्षाओं की ईमानदारी से करवाने की इस जटिल गुत्थी को सुलझाने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। आने वाला भारत डिजिटल होने जा रहा है। यहां शिक्षा के अलग-अलग आयामों में आमूलचूल परिवर्तन होगा। एआई तकनीकें सामने आ रही हैं। साइबर शक्ति बढ़ रही है। इन्हें सीखने का क्रम चलता रहे और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो हर वर्ष ऐसे एक देश एक परीक्षा जैसे आयोजन निरापद ढंग से पूरे हो सकेंगे।?

माध्यमिक स्तर पर बच्चों की पढ़ाई का गिरता स्तर

तू ना सम्हाले तो हमें कौन सम्हाले..!

राजनीतिक विशलेषक एवं पत्रकार जौनपुर यूपी

पंकज सीबी मिश्रा

एक दावे के अनुसार नीति आयोग की रिपोर्टकी रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक दशक में भारत में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जिससे बच्चों के नामांकन में 2.26 करोड़ की कमी आई है। सरकारी स्कूलों की संख्या 11.07 लाख से घटकर 10.13 लाख हो गई है। ये आंकड़े बेहद चौकाने वाले हैं और ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा के सामने खड़े कई बड़े संकटों को उजागर करते हैं। प्राथमिक स्कूलों में भरे लाखों फर्जी शिक्षक अब भी शासन के पकड़ से दूर है जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सरकारी स्कूलों की संख्या साल 2014-15 में 11.07 लाख थी, जो साल 2024-25 में घटकर 10.13 लाख रह गई। इसी दौरान, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या भी 83,000 से घटकर 79,000 पर आ गई। प्राइमरी क्लास (पहली से पांचवी) में स्कूल छोड़ने की दर जहाँ 0.3त्न है।

वहीं अपर प्राइमरी (छठी से आठवीं) में यह बढ़कर 3.5त्न हो जाती है। माध्यमिक स्तर (9वीं और 10वीं) तक पहुंचते-पहुंचते यह 11.5त्न के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। इसके अलावा, आठवीं से नौवीं कक्षा में जाने वाले छात्रों की दर भी साल 2014-15 के 91.58त्न से घटकर साल 2024-25 में 86.6त्न रह गई है। रिपोर्ट ने माध्यमिक स्तर पर बच्चों की पढ़ाई के स्तर (लर्निंग गैप्स) पर भी सवाल उठाए हैं। जांच में पाया गया कि कक्षा 9वीं के कई छात्र न केवल बीजगणित और ज्यामिति जैसे कठिन विषयों से जूझ रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रतिशत, भिन्न और अनुपात जैसी बुनियादी अवधारणाओं को समझने में भी दिक्कत आ रही है क्यूंकि हम जैसे योग्य युवा बेरोजगार स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे, ठेला लगा रहे और फर्जी शिक्षक सरकारी स्कूलों में मौज मार रहे। सोशल मीडिया पर अब इसे लेकर ट्रोलिंग खूब बढ़ा है और इसके पीछे किन लोगों का समर्थन रहा है, यह जनता जानती है। वैसे अगर संरचनात्मक गड़बड़ियों पर सरकार से ही जवाब मांगा जाएगा, इस पर सरकार के लोग चिढ़ते क्यों हैं, यह समझ से परे है।

हाल ही में एक वाक़या उत्तरप्रदेश से सामने आया है, जब पत्रकार ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से सवाल किया कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन से पहले ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कई जगह से धंस गया है। तो दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब दिया कि इसमें कौन सी नयी बात है, आप सड़क खुद बनवा लो। उन्होंने सड़कों की टूट-फूट और मरम्मत को प्रक्रिया का हिस्सा बताया। बेशक सड़कें टूटती हैं, उनमें गड्ढे बनते हैं, लेकिन जब वे कई बरसों तक इस्तेमाल हो जाएं तब उनकी मरम्मत की नौबत आनी चाहिए। अगर उद्घाटन से पहले या शुरु होने के चंद दिनों में सड़कें, पुल या कोई भी इमारत टूटे तो ज़ाहिर है कि उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस समय अकेले महाराष्ट्र या उत्तरप्रदेश से नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली कई राज्यों में कहीं सड़कें टूटीं, कहीं एयरपोर्ट पानी-पानी हुआ, कहीं स्टेशन पर पंखे से पानी गिरने लगा। ऐसी तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि विकास के नाम पर जनता के दिए टैक्स से जो भारी-भरकम परियोजनाएं बन रही हैं, उनकी लागत का बड़ा हिस्सा भाजपा नेताओं, अधिकारियों या ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता ने इस भ्रष्टाचार को अब सामान्य आचरण मानकर स्वीकार कर लिया है। फिर भी कभी सवाल उठाए जाते हैं तो ऐसे ही जवाब मिलते हैं कि 'खुद बनवा लो या जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो सवाल पूछ रहे हैं।'

अब तो सरकार की आलोचना को व्यक्तिगत आलोचना माना जाने लगा है । जबकि हाल ही में महाराष्ट्र में ही जस्टिस माधव जामदार ने सरकार विरोधी नारे लगाने पर एक व्यक्ति को तड़ीपार करने के आदेश पर पुलिस को फटकार लगाई और साफ़ कहा कि किसी नेता के ख़िलाफ़ नारे लगाना देशविरोधी काम नहीं है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। लचर और दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सरकार के खिलाफ नारे आम बात है और जिन बच्चों ने दोबारा परीक्षा देने के तनाव से या पेपर लीक होने के अवसाद में अपनी जान दे दी, उनके साथ इंसाफ़ किस तरह होगा, यह एक बड़ा सवाल है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कम से कम 19 बच्चे अपनी जान दे चुके हैं और यह संख्या यहीं रुक जाए ङ्क ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।बच्चों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही कुंठा भरनी शुरु हो जाती है। हर महीने लिए जाने वाले क्लास टेस्ट से लेकर छमाही और वार्षिक इम्तिहानों तक बच्चों पर दबाव बनाया जाता है कि अच्छे अंक लाना और प्रथम आना ही कामयाबी का एकमात्र रास्ता है, उसके अलावा जीवन में कुछ और बचा ही नहीं है। इस भावना के साथ पढ़ाई करने वाले बच्चों का मन हताशा की तरफ बढने लगता है और यही हताशा बोर्ड परीक्षाओं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने पर जीवन ख़त्म करने के विकल्प की तरफ धकेल देती है।

आज़ादी के इतने सालों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई किस्म के प्रयोग हुए, कई पद्धतियां अपनाई गईं, लेकिन राजनेताओं ने शिक्षा और परीक्षा की खामियों पर कभी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करना जरूरी नहीं समझा।अब राहुल गांधी ने कोटा से इसकी शुरुआत की है। उनके भाषण में इसी बात पर ज़ोर दिया गया कि हम बच्चों में रिजेक्शन यानी खारिज होने का डर भर देते हैं, जो ग़लत है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जंतर-मंतर पर फिर धरना शुरु किया है। इस बार पुलिस की तय की गई समयसीमा को मानने से प्रदर्शनकारियों ने इंकार कर दिया और शनिवार से लेकर सोमवार को इन पंक्तियों के लिखे जाने तक धरना जारी ही है। धरनास्थल पर खाने-पीने की व्यवस्था करने के लिए मोहम्मद जुनैद नाम के एक शख्स लगातार कर रहे हैं, सोमवार को उनके पैर छूकर अभिजित दिपके ने उन्हें शुक्रिया कहा।

इस मौके पर इंकलाब जिंदाबाद और ब्राह्मण वाद हो बर्बाद जैसे नारे भी सुनें गए । गौरतलब है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए शुरु किया गया आंदोलन सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ भी रहा है। वहीं दिपके ने इस आंदोलन से किसानों को भी जुड़ने की अपील की थी। अब भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी समूह ने ऐलान किया है कि युवाओं के भविष्य और उन्हें इंसाफ़ दिलाने के लिए भाकियू कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करेगा। सरकार की गैर जिम्मेदाराना रणनीति के विपरीत विपक्ष और आम जनता का बड़ा वर्ग शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए साथ आए तो इसे एक सकारात्मक बदलाव की तरह देखा जाए और सुधार हो सके।

अपनी समस्या हमें बतायें

आपके साथ या आपके आस-पास कोई घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, जुर्म हुआ है या उत्पीड़न हुआ है अथवा आपके क्षेत्र की समस्या है और आपकी समस्या जायज है तो आपकी समस्याओ के समाधान हेतु सम्बन्धित उच्च अधिकारियों एवं शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के लिये बी पी एस न्यूज आपके साथ है। आपकी खबर शत् प्रतिशत प्रकाशित की जायेगी। एवं आपका नाम व नम्बर आपके अनुसार प्रकाशित या पूर्णतया गुप्त रखा जायेगा।

दिये गये नम्बर पर काल करें या हमें ई मेल करें।

फोन नं.- 8423454502,

bps.knp786@gmail.com

आवश्यक सूचना

प्रिय ग्राहकों/विज्ञापनदाताओ को सूचित किया जाता है कि बीपीएस न्यूज समाचार पत्र मे नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। कृपया चेक/डी.डी. बी पी एस न्यूज के नाम से ही चेक आदि भेजें। नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। नगद भुगतान करने पर विज्ञापनदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- संपादक

आवश्यकता है

बी पी एस न्यूज राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र व ऑनलाइन न्यूज चैनल (पोर्टल) के लिये समस्त तहसीलों एवं ब्लाक स्तर पर ब्यूरो चीफ, संवाददाताओ, छायाकार तथा विज्ञापन प्रतिनिधियों युवक-युवतियों की आवश्यकता है।

संपर्क करें -:मो.: 8423454502

email:bps.knp786@gmail.com

जन्मदिन की हार्दिक बधाई

कानपुर। बीपीएस न्यूज संवाददाता तनवीर नियाज़ का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ नौबस्ता स्थित कार्यालय में मनाया गया।

महिला सम्मान से जुड़े गंभीर मामलों में समझौता स्वीकार्य नहीं: विजया रहाटकर

» दहेज उत्पीड़न व महिला हिंसा के मामलों में होगी त्वरित और कठोर कार्रवाई

» राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार महिला जनसुनवाई कार्यक्रम किया गया आयोजित

कानपुर। राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्ष विजया रहाटकर की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के नवीन सभागार में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम ÷राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार÷ आयोजित किया गया। जनसुनवाई में महिलाओं से संबंधित कुल 61 प्रकरणों पर सुनवाई की गई।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान, संयुक्त पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) विवेक चतुर्वेदी सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।जनसुनवाई के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बताया कि सुनवाई के लिए कुल 61 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें 40 प्रकरण पूर्व से राष्ट्रीय महिला आयोग में पंजीकृत थे, जिनकी प्रत्यक्ष सुनवाई की गई। इसके अतिरिक्त आयोग के कानपुर आगमन की जानकारी मिलने पर 21 नई वॉक-इन शिकायतें भी प्राप्त हुईं।उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में सर्वाधिक मामले पारिवारिक विवादों से संबंधित रहे, जिनमें पति-पत्नी के बीच विवाद तथा परिवार के स्तर पर महिलाओं के उत्पीड़न के प्रकरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं परिवार और समाज के दबाव में लंबे समय तक उत्पीड़न सहती रहती हैं तथा यह सोचकर चुप रहती हैं कि स्थिति में सुधार हो जाएगा। ऐसे मामलों में महिलाओं को समयबद्ध राहत और न्याय दिलाना आवश्यक है।विजया रहाटकर ने कहा कि जनसुनवाई में यौन उत्पीड़न तथा साइबर अपराध से जुड़े प्रकरण भी सामने आए हैं। आयोग ने कई मामलों में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। एक गंभीर प्रकरण में परिवार द्वारा आपसी समझौते का प्रयास किया गया था, लेकिन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान सर्वोपरि हैं तथा बलात्कार एवं अन्य गंभीर अपराधों में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। संबंधित प्रकरण में पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने बताया कि एक अन्य लंबे समय से लंबित मामले में महिला के साथ लगातार मारपीट और उत्पीड़न की शिकायत सामने आई। इस प्रकरण में भी पुलिस को आरोपित के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने तथा तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। दहेज उत्पीड़न और दहेज के कारण महिलाओं की हत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में दहेज प्रतिषेध के लिए प्रभावी कानून होने के बावजूद विभिन्न रूपों में दहेज की मांग की जाती है, जिसके कारण महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और कई बार उनकी जान तक चली जाती है।उन्होंने कहा कि हाल में सामने आए दहेज उत्पीड़न के कुछ गंभीर मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। संबंधित राज्यों की पुलिस को आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच, कठोर कार्रवाई तथा मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग भोपाल और गाजियाबाद सहित अन्य मामलों की भी निगरानी कर रहा है।

लंबित मामलों के संबंध में विजया रहाटकर ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनकी सुनवाई करना एक बड़ी चुनौती है। शिकायतों के निस्तारण में पुलिस रिपोर्ट, अभिलेखों तथा विभिन्न विभागों से समन्वय के कारण समय लग सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए आयोग ने जमीनी स्तर पर पहुंचकर प्रत्यक्ष जनसुनवाई की व्यवस्था शुरू की है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अब केवल कार्यालय स्तर पर शिकायतों की सुनवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न राज्यों, जनपदों और गांवों में जाकर महिलाओं की समस्याएं सुन रहा है। गत एक वर्ष में आयोग द्वारा सवा दो सौ से अधिक प्रत्यक्ष जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। आयोग का प्रयास है कि महिलाओं को उनके क्षेत्र में ही सुनवाई का अवसर मिले और उन्हें त्वरित न्याय एवं राहत उपलब्ध कराई जा सके।

धनकुट्टी में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

राधा स्वामी ट्रेड लिंक से 535 किलो चाय सीज

जांच के लिए 2 सैंपल भेजे गए प्रयोगशाला

» बीपीएस न्यूज/विशेष संवाददाता

कानपुर। मिलावटखोरों और मानकों की अनदेखी करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) कानपुर नगर के कड़े निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने धनकुट्टी स्थित 'राधा स्वामी ट्रेड लिंक' का औचक निरीक्षण किया।अचानक हुई इस छापेमारी से बाजार में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने परिसर में बिक्री के लिए रखी गई चाय की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसके दो अलग-अलग नमूने (सैंपल) संग्रहित किए। इन नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है।इसके साथ ही, टीम ने मौके पर बची हुई शेष 535 किलोग्राम चाय को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया। सीज की गई इस चाय की कुल अनुमानित कीमत 94,890 रुपये बताई जा रही है। खाद्य अधिकारियों ने विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए सीज किए गए माल को संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया है। सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने कहा- कि नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना हर संस्थान की जिम्मेदारी: विजया

सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में 'पॉश अधिनियम' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

कानपुर। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानपुर नगर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यहाँ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, 2013 के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। जिनमें बबीता सिंह (सदस्य, राज्य महिला आयोग), अनीता गुप्ता (सदस्य, राज्य महिला आयोग), सरोज कुरील (माननीय विधायक, घाटमपुर), पुनीत मिश्रा (उपनिदेशक, महिला कल्याण विभाग) इसके साथ ही विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक भी इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बने।सरल भाषा में समझे पॉश अधिनियम के कड़े प्रावधानअपने संबोधन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहटकर ने 'पॉश कानून' को बेहद सरल और सहज भाषा में सभी के सामने रखा।उन्होंने अधिनियम के प्रमुख कानूनी पहलुओं को समझाते हुए दो मुख्य स्तंभों पर विशेष जोर दिया 1. आंतरिक शिकायत समिति इसका गठन, कार्यप्रणाली और संस्थानों में इसकी अनिवार्य भूमिका। 2. स्थानीय समिति जिला स्तर पर काम करने वाली इस समिति की शिकायत निवारण प्रक्रिया।प्रत्येक कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और बिना किसी भेदभाव वाला वातावरण तैयार करना केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि हर संस्थान की नैतिक जिम्मेदारी है।

अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया सुरक्षा का संकल्प इस कार्यशाला में कानपुर के विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उपस्थित जनों ने न केवल पॉश अधिनियम से जुड़ी बारीकियों और महत्वपूर्ण जानकारियों को समझा, बल्कि अपने-अपने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को पूरी निष्ठा से लागू करने का सामूहिक संकल्प भी लिया। यह कार्यशाला कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय प्रयास साबित हुई।

नागेंद्र स्वरूप आडोटोरियम में कार्यशाला 'शक्ति और सुरक्षा' का हुआ शुभारंभ

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आयोजित एडवांस जेंडर सेंसटिव पुलिसिंग का 2 दिवसीय कार्यशाला 'शक्ति और सुरक्षा'का शुभारंभ नागेंद्र स्वरूप आडोटोरियम में किया गया।कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर और विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ बबीता सिंह चौहान मौजूद रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और -सुभाष चन्द्र द्विवेदी आईजी द्वारा बुके देकर और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कंपैशनेट कॉप शक्ति और सुरक्षा पुस्तक का विमोचन किया गया। दरअसल इस कार्यक्रम की शुरुआत 9, 10 जून को? गाजियाबाद में हुयी थी और आज दूसरा है कार्यक्रम कानपुर नगर में आयोजित किया गया है।

जिसमें 17 जिलो की पुलिस टीम सम्मिलित हुयी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर ने अपने संबोधन मे कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है। लेकिन पुलिस एक सबसे पहली कड़ी है। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पुलिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी महिला के लिए थाना गवर्मेंट आफिस नहीं होता है बल्कि न्याय की पहली उम्मीद होता है।उनको भरोसा होता है कि पुलिस न्याय करेगी। महिलाओं का विश्वास और उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि वातावरण अच्छा हो, डिसिप्लिन हो, पीड़िता निराश नहीं होगी, नियम के साथ संवेदनशीलता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने महिलाए पुलिस की शिकायत लेकर आती है, कि पुलिस बैठा कर रखती है इस पर पुलिस ध्यान दें। पति पत्नी के मामलों को? लेकर पुलिस धैर्य से काम ले। त्वरित मुकदमा दर्ज न करने की बजाय मामले का निस्तारण कराए।

बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले प्रधानाचार्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार

» अपने रसूख का रौब दिखाकर लोगों के साथ समझौते के लिए पहुंचा चौकी

» अभिभावकों और लोगों के भारी विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार

कानपुर। पनकी क्षेत्र स्थित एक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घबराई बच्ची स्कूल जाने से डर रही थी, माता-पिता के पूंछने पर उसे सारा वृस्तांत बताया। इतना ही नही अन्य बच्चियों के साथ भी प्रधानाचार्य ने अश्लील हरकत की। अभिभावकों और स्थानीय लोगो के आक्रोश और भीषण विरोध के बाद पुलिस ने किसी प्रकार मामला दर्ज कर आरोपी प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार मामला पनकी थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि पनकी के शिवराज नगर गंगागंज कॉलोनी में एक प्री-स्कूल चलाने वाला प्रधानाचार्च 48 ब्रजेश पाल बिच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता है। एक बच्ची के द्वारा स्कूल जाने से मना करने पर माता-पिता को जब सच्चाई बताई और कहा कि उसकी दो सहेलियों को भी प्रधानाचार्य परेशान करता है। जब दो अन्य बच्चियों से जानकारी की गयी तो बात सच निकली। इसके बाद सभी अभिभावक और आक्रोशित स्थानीय लोग चौकी पहुंचे और प्रधानाचार्य की शिकायत करते हुए गिरफ्तार करने को कहा। प्रधनाचार्य ब्रजेशपाल अपने गुर्गो के साथ चौकी पहुंचा और दबाव में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन उत्तेजित भीड़ को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं थानाध्यक्ष पनकी का कहना है कि आरोपी ब्रजेश पाल को गिरफ्तार कर उसपर पास्को एक्ट की कार्यवाई की गयी है।

सुबह जनता दर्शन में शिकायत, शाम तक चकरोड से हटा अतिक्रमण

» डीएम के निर्देश पर तत्काल मौके पर पहुंची राजस्व-पुलिस टीम, सीमांकन कर आवागमन कराया सुचारु

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। ग्राम धरछुआ में चकरोड पर अतिक्रमण से बाधित आवागमन की शिकायत शुक्रवार सुबह जिलाधिकारी के जनता दर्शन में पहुंची तो शाम तक उसका समाधान हो गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में चकरोड का सीमांकन कर अतिक्रमण हटवाया और आवागमन सुचारु करा दिया।

ग्राम धरछुआ निवासी गोरेलाल ने शुक्रवार को जिलाधिकारी के जनता दर्शन में शिकायत की कि गाटा संख्या 607 में स्थित चकरोड पर अतिक्रमण से आवागमन बाधित हो रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त रास्ते से आसपास के गांवों के लोगों और पावर प्लांट के कर्मचारियों का आवागमन होता है। चकरोड बाधित होने से उन्हें अपने खेत तक पहुंचने और कृषि कार्य में भी परेशानी हो रही थी।

जिलाधिकारी ने शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर भेजकर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्व अभिलेखों की जांच में गाटा संख्या 607 चकरोड के रूप में दर्ज पाया गया। टीम ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में चकरोड का सीमांकन किया और अतिक्रमण वाले हिस्से को चिह्नित कर कब्जामुक्त करा दिया।

एसडीएम घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह ने बताया कि सीमांकन के बाद चकरोड को अतिक्रमणमुक्त करा दिया गया है और वर्तमान में आवागमन पूरी तरह सुचारु है। दोनों पक्षों को भविष्य में चकरोड पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करने तथा आवागमन में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों पक्ष कार्रवाई से संतुष्ट हैं।

सिटी हेल्थ एक्शन प्लान, टीबी उन्मूलन एवं टीकाकरण अभियान की समीक्षा

लापरवाही पर डीएम सख्त, खराब प्रदर्शन पर वेतन रोकने के दिए निर्देश

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिला टीबी टास्क फोर्स कमेटी एवं सिटी हेल्थ एक्शन प्लान कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (टीबी) एवं नियमित टीकाकरण अभियान की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

टीबी स्टीयरिंग कमेटी की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मसवानपुर के डॉ. प्रीतम द्वारा टीबी स्क्रीनिंग का कार्य सबसे कम किया गया है तथा इसके संबंध में वे कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा कार्य में अपेक्षित सुधार होने तक वेतन रोकने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त एमओआईसी को निर्देशित किया कि हाई-रिस्क क्षेत्रों में विशेष टीबी जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि टीबी के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए टीबी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-6666 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि टीबी मरीजों की नियमित निगरानी के लिए जनपद के युवा मंगल दलों को सक्रिय किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक मरीज समय पर और नियमित रूप से दवा ले रहा है। साथ ही मरीजों को उपचार की पूरी अवधि तक दवा लेने के लिए लगातार प्रेरित किया जाए, ताकि जनपद को समयबद्ध रूप से टीबी मुक्त बनाया जा सके।

बैठक में नियमित टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद के सभी एमओआईसी अपने-अपने क्षेत्रों में आशा एवं एएनएम के माध्यम से शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनपद का एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक जोन के लिए एक जोनल अधिकारी नामित किया जाए, जो प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को आयोजित नियमित टीकाकरण सत्रों की समीक्षा करेगा।

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को एमआर (मीजल्स-रूबेला) वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगाई जाए, ताकि उन्हें खसरा एवं रूबेला जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए ड्यू-लिस्ट तैयार कर छूटे हुए बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे को बुखार के साथ शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई दें तो अभिभावक तत्काल उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करें तथा आवश्यक उपचार एवं टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने पुनः निर्देश दिए कि कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरि दत्त नेमी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुबोध प्रकाश, डॉ. एस.पी. यादव, जेसीआई संस्था से डॉ. विभोर कौशिक, सुश्री हुडा ज़हरा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा,जर्जर सड़क दुर्घटना का कारण, खंती में उतरी स्कूल बस

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। सरसौल के घाघूखेड़ा गांव में जर्जर सड़क एक बार फिर हादसे की वजह बन गई। सड़क धंसने और खराब मार्ग के कारण स्कूली बस खंती में उतर गई।

बस में सवार तीनों बच्चे सुरक्षित रहे। चालक की सूझबूझ से बस पलटने से बच गई और बड़ा हादसा टल गया।

घटना के बाद ग्रामीणों ने जिम्मेदार प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जल्द सड़क दुरुस्त कराने की मांग की है।

खाकी वर्दीधारी पर्यावरण प्रहरी अनूप मिश्रा के 'बरगद बचाओ महाअभियान' को मिल रहा व्यापक जन समर्थन

सैकड़ों महिलाओं ने संभाली पर्यावरण संरक्षण की कमान, मरीजों के लिए स्वच्छ हवा और हरियाली का संकल्प

» बीपीएस न्यूज

उन्नाव। उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश भी दे रही है , इस बात को उन्नाव पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी अनूप मिश्रा ने अपने हरित कार्यों से सच्चाई में तब्दील कर दिखाया है द्य प्रकृति संरक्षण के इसी संदेश को साकार करते हुए उमाशंकर दीक्षित संयुक्त चिकित्सालय (जिला अस्पताल) उन्नाव आज हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का साक्षी बना। जिला पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी अनूप मिश्रा अपूर्व द्वारा पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे व्यापक जन -अभियान बरगद बचाओ महाअभियान के तहत उन्नाव जिले में लोगों द्वारा वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है, इसी अभियान के समर्थन में श्री जी सामाजिक सेवा समिति के सहयोग से जिला अस्पताल परिसर में 100 से अधिक छायादार, फलदार एवं औषधीय पौधों का जिला चिकित्सालय में रोपण किया गया।बरगद का पौधा लगा कर आज के पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई ।

अभियान संयोजक अनूप मिश्रा अपूर्व के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस), डॉ. सुनील कुमार शुक्ला , डा. संजीव कुमार एवं श्री जी सामाजिक सेवा समिति की अध्यक्षा, संस्था की संस्थापिका व अध्यक्षा मंजू अवस्थी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर बरगद, पीपल, नीम, बेल, आँवला और अमरूद सहित अनेक जीवनदायी पौधे लगाए। पर्यावरणविद अनूप मिश्रा अपूर्व ने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छ हवा, प्राकृतिक छाया और हरित वातावरण मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रत्येक अस्पताल परिसर में अधिक से अधिक छायादार एवं औषधीय पौधे लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बरगद बचाओ महाअभियान केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनपद के प्राचीन बरगदों और अन्य जीवनदायी वृक्षों को बचाने का व्यापक जनआंदोलन है।सीएमएस डॉ. एस. के. शुक्ला ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि हरित अस्पताल की अवधारणा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आने वाले वर्षों में यह परिसर मरीजों और उनके परिजनों के लिए शीतल, स्वच्छ और प्रेरणादायी वातावरण उपलब्ध करा सके।वृक्षारोपण अभियान में मंजू अवस्थी, मनीता सेंगर, अरुणा तिवारी, नीलम श्रीवास्तव, पूर्णिमा अवस्थी, दीपाली मिश्रा, मीनू सिंह, माया वर्मा, गायत्री मिश्रा, शिल्पा मिश्रा, ज्योति गौर, प्रीति शुक्ला, नीतू शर्मा, बिमलेश मिश्रा, सीमा सिंह, अविका अवस्थी सहित सैकड़ों महिलाओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा, एक दर्जन से अधिक युवक-युवतियां हिरासत में

कॉल सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन मैच और अन्य गतिविधियों का हो रहा था संचालन

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। कमिश्नरेट के पश्चमी जोन कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कैलाश विहार में संचालित एक संदिग्ध ऑनलाइन कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी कर एक दर्जन से अधिक युवक-युवतियों को हिरासत में लिया है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि कॉल सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन मैच और अन्य गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर सोमवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा और वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। छापेमारी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज भी जांच के दायरे में लिए गए हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए युवक-युवतियों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में कॉल सेंटर की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। मामले में कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव तिवारी और रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय की टीम जांच में जुटी है।

डीसीपी पश्चिम द्वारा पूरे मामले का खुलासा किए जाने की संभावना है। पुलिस कॉल सेंटर के संचालन, वित्तीय लेनदेन और इससे जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

जल निगम के कार्य के दौरान टूटी पाइपलाइन का विधायक ने किया निरीक्षण

- समय से पानी चालू नहीं हुआ, तो लटका देंगे उल्टा
- जनता को परेशान करने वाले अधिकारी कानपुर छोड़कर भागने के लिए तैयार रहें
- पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

कानपुर। गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डबल पुलिया के नीचे 3 दिन पहले जल निगम के कर्मचारियों ने मुख्य पेयजल बड़ी लाइन के कार्य निर्माण के द्वारा तोड़ देने से बैंक का लीकेज हो गया था और पूरे शास्त्री नगर, विजयनगर सहित डेढ़ लाख से ज्यादा लोग, पानी के लिए तब से लगातार आज तक त्राहिमाम कर रहे हैं।

कार्य प्रारंभ होते ही, जल निगम की कार्यदायी संस्था, इंजीनियरों और टेक्निकल टीम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस घोर लापरवाही के कारण क्षेत्र की मुख्य पेयजल पाइपलाइन टूट गई, जिससे स्थानीय जनता के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र मैथानी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकस्मिक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य की कछुआ गति और अधिकारियों की उदासीनता को देखकर विधायक जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने जल निगम के अधिशासी अभियंता प्रवीण यादव, सहायक अभियंतासिकंदर पटेल और अवर अभियंता अनिल कुमार को कार्यस्थल पर ही, सबके सामने कड़ी फटकार लगाई।विधायक द्वारा अधिकारियों को दी गई सख्त चेतावनी कहा कल सुबह तक हर हाल में आपूर्ति बहाल हो- विधायक ने अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कल सुबह तक, शास्त्री नगर और विजयनगर सहित, हमारे सभी प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई हर हाल में चालू हो जानी चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो उन्होंने सोची भी नहीं होगी।उन्होंने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, ÷अगर आप लोग काम अधूरा छोड़कर या साइट से भागने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिएगा कि आपको कानपुर छोड़कर भागना पड़ जाएगा।विधायक ने अधिशासी अभियंता को फटकारते हुए कहा कि, मोदी जी और योगी जी, जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने के लिए संकल्पबद्ध है,और जल जीवन मिशन पर भी, दिन रात काम कर रहे हैं। परंतु कानपुर में आपकी लापरवाही के कारण जनता को सफर करने पर, मजबूर होना पड़ रहा है। हम किसी भी कीमत पर, जनता को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते। विधायक ने स्पष्ट किया कि पानी जनता की मूलभूत और सबसे अनिवार्य सुविधा है। इसके बिना जीवन नामुमकिन है। जनता को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसाने वाले अधिकारियों के दिमाग ठिकाने लगाना उन्हें अच्छी तरह आता है।कहा आज चाहे पूरी रात, आज आपको काम करना पड़े, आप करें। परन्तु कल हर हाल में मैं,पानी चालू होता देखना चाहता हूं। इसे आप मेरा आग्रह भी मान लीजिए और चेतावनी भी। ?मौके पर ही शुरू कराया युद्धस्तर पर काम। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सिर्फ डांट-फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि खुद मौके पर डटकर अपनी मौजूदगी में काम को गति दी। उन्होंने तकनीकी टीम को निर्देशित किया कि युद्धस्तर पर काम करके जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्रीय जनता को पुनः सुचारू रूप से जलापूर्ति मिल सके। उन्होंने साफ कहा कि जनता के हक और सहूलियत के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और लापरवाह अफसरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे।मौके पर विधायक सुरेंद्र मैथानी एवं जल निगम के अधिशासी अभियंता प्रवीण यादव एवं सहायक अभियंता सिकंदर पटेल एवं अवर अभियंता अनिल कुमार तथा पूर्व पार्षद प्रेम सिंह एवं मंडल उपाध्यक्ष सतीश शुक्ला तथा क्षेत्रीय लोग उपस्थित थे।

मसाला फैक्ट्रियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा छापा, भारी मात्रा में मिलावटी व संदेहास्पद मसाले और अचार किए गए सीज

विशेष अभियान के तहत श्री गुरुकृपा मसाले और हरिकिशन मसाला यूनिट पर बड़ी कार्रवाई, करीब 4.5 लाख रुपये का माल किया जब्त

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के आदेश पर तथा सहायक आयुक्त (खाद्य) कानपुर नगर के कुशल निर्देशन में शहर में मिलावटी व घटिया मसालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दो अलग-अलग मसाला निर्माण यूनिटों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है।

कांप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स-टीम ने सबसे पहले रामपुरम श्याम नगर स्थित श्री गुरुकृपा (स्त्य) मसाले की निर्माण यूनिट पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां बेहद अस्वस्थकर परिस्थितियां पाई गईं और मसालों का रखरखाव भी मानकों के अनुरूप नहीं था।

यहाँ निम्नलिखित बड़ी कार्रवाइयां की गईं 1,050 किलोग्राम मिक्स अचार सीज- परिसर में 5-5 किलो के लगभग 210 डिब्बों में अस्वस्थकर स्थितियों में रखा गया रंगीन अचार मिला। टीम ने इसका नमूना लिया और शेष 1049 किलोग्राम अचार को तुरंत सीज कर दिया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपये आंकी गई है।

लेबलिंग में हेराफेरी (90 किलो रेड चिली पाउडर सीज) परिसर में मौजूद रेड चिली पाउडर के डिब्बों पर बैच नंबर आदि अनिवार्य जानकारियां गायब थीं। नियम उल्लंघन पर नमूना लेकर 90 किलोग्राम मिर्च पाउडर (कीमत लगभग 22,500 रुपये) सीज किया गया।

मिथ्या छाप धनिया पाउडर- धनिया पाउडर के पैकेटों पर भी भ्रामक व गलत जानकारियां (मिथ्या छाप) पाई गईं। नमूना संकलित कर 40 किलोग्राम धनिया पाउडर (कीमत 8,000) जब्त किया गया।

घटिया मिर्च पाउडर व हल्दी- खराब गुणवत्ता की आशंका पर 264 किलोग्राम मिर्च पाउडर (कीमत 66,000) और संदेह के घेरे में आए 5 गत्तों में रखे 50 किलोग्राम हल्दी पाउडर (कीमत 22,000) का नमूना लेकर उन्हें सीज कर दिया गया।

4 बोरियों में बंद मिर्च की थैलियां जब्त-परिसर से 500 ग्राम के 240 पैकेटों में बंद कुल 120 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर (कीमत 36,000) का सैंपल लेकर पूरी खेप सीज की गई।

अपट्रान- 'हरिकिशन मसाला यूनिट' पर भी कसा शिकंजा

कार्रवाई के दूसरे चरण में खाद्य विभाग की टीम ने अपट्रान स्थित हरिकिशन के मसाला यूनिट परिसर में छापा मारा।

यहाँ मसालों में मिलावट का एक बड़ा खेल सामने आया

चावल के रूप में मिला 'एडल्टरेंट' (अपमिश्रक)- परिसर में मसालों के साथ-साथ मिलावट के लिए भारी मात्रा में चावल भंडारित पाया गया।

सैंपलिंग और जब्ती-टीम ने यहाँ से पिसा धनिया, पिसा मिर्च और एडल्टरेंट (चावल) सहित कुल 3 नमूने संग्रहित किए। इसके साथ ही 280 किलोग्राम पिसा धनिया (अनुमानित कीमत 28,000) सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया।सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने कहा- सभी एकत्रित नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम , 2006 के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी मिलावटखोर को बख्शा नहीं जाएगा।

जनसमस्याओं के समाधान व मार्ग निर्माण हेतु जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। उत्तर प्रदेश कल्याणकारी व्यापार मंडल के प्रदेश प्रभारी, जोनल हेड कानपुर संदीप पाण्डेय के नेतृत्व में एवं कानपुर दक्षिण जोन के जोन प्रभारी पूर्व पार्षद हरिशंकर गुप्ता के संचालन में एक ज्ञापन कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय में उनकी अनुपस्थिति में एसीएम सप्तम को सौंपा गया।

ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई कि कानपुर दक्षिण के प्रमुख व्यापारिक एवं आवासीय क्षेत्र किदवई नगर से बारादेवी जाने वाला मुख्य मार्ग अत्यंत जर्जर एवं बदहाल स्थिति में है। अवगत कराया गया कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लंबे समय से दोनों ओर सड़क खोदकर छोड़ दी गई है, जिससे आम नागरिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिदिन भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धूल, कीचड़ और उड़ती मिट्टी के कारण आसपास के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है।

व्यापारियों ने यह भी बताया कि मार्ग पर अनेक स्थानों पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं, सीवर एवं जल निगम के चैंबर धंस चुके हैं, जिससे वाहन चालक आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बरसात के दौरान सड़क पर जलभराव होने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है तथा राहगीरों का निकलना मुश्किल हो जाता है।

मांग की गई कि पूरे मार्ग पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल ठीक कराया जाए, धंसे हुए चैंबरों का पुनर्निर्माण कराया जाए, सड़क निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर पूर्ण कराया जाए तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। साथ ही सड़क किनारे मलबा हटाकर नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था कराई जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही सड़क निर्माण एवं अन्य जनसमस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्र के व्यापारी एवं नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं प्रशासन की होगी।

कानपुर के 11,484 शिक्षक व शिक्षा कार्मिकों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज

कानपुर। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के साथ कानपुर नगर के 11,484 शिक्षक एवं शिक्षा कार्मिकों और उनके आश्रितों को ?5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। योजना से जनपद के 5,936 शिक्षक, 1,968 शिक्षामित्र, 122 अनुदेशक, 20 विशेष शिक्षक (सीडब्ल्यूएसएन) तथा 3,438 रसोइये लाभान्वित होंगे।बुधवार को मर्चेंट चेंबर हॉल में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने शिक्षकों को योजना के कार्ड वितरित किए। इससे पूर्व वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। मर्चेंट चेंबर के साथ बिल्हौर, घाटमपुर और नरवल तहसील में भी समानांतर कार्यक्रम आयोजित कर कार्ड वितरित किए गए।

कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। लंबे समय से शिक्षकों की मांग रही कैशलेस चिकित्सा योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साकार किया है। पूर्व की सरकारों ने शिक्षकों की चिंता नहीं की, जबकि वर्तमान सरकार ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब शिक्षकों एवं शिक्षा कार्मिकों के परिवारों को उपचार की चिंता से मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 12 लाख से अधिक शिक्षक एवं शिक्षा कार्मिक योजना से लाभान्वित होंगे और इसके संचालन पर राज्य सरकार लगभग ?450 करोड़ व्यय करेगी।

उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खातों में सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। उन्होंने अभिभावकों से धनराशि का उपयोग बच्चों की निर्धारित शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए करने तथा शिक्षकों से स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत विद्यालय से बाहर प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित कराने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु प्रति छात्र ?1,200 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जारी की गई। इसके लिए ?1,300 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ किए गए एमओयू के तहत शिक्षकों को ?30 लाख से ?80 लाख तक का बीमा सुरक्षा कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। दुर्घटना की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा के साथ बच्चों की शिक्षा और पुत्री के विवाह जैसी आवश्यकताओं में भी सहायता का प्रावधान है।योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र कार्मिकों को विशेष पोर्टल पर स्वयं एवं अपने आश्रितों का विवरण दर्ज करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से सत्यापन और ई-केवाईसी के बाद कैशलेस चिकित्सा कार्ड जनरेट होगा।

कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी, विधायक नीलिमा कटियार, विधायक महेश त्रिवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण,श्री सुरेंद्र अवस्थी, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन ने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए।

इस अवसर पर एडी बेसिक शिवेंद्र प्रताप सिंह, डीआईओएस प्रवीण कुमार तिवारी, एडीआईओएस प्रशांत कुमार द्विवेदी, बीएसए हरिओम सिंह सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

चीन की जूता फैक्ट्री में अग्निकांड, 28 मजदूरों की दर्दनाक मौत

फैक्ट्री में फंसे 237 लोगों में से 213 को बचाया गया, मालिक समेत जिम्मेदार अधिकारी हिरासत में

» बीपीएस न्यूज

नई दिल्ली। चीन के पूर्वी फुजियान प्रांत के जिनजियांग शहर स्थित एक जूता निर्माण फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर भीषण आग लगने से कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय फैक्ट्री में 237 कर्मचारी और दो आगंतुक मौजूद थे। बचाव दल ने 213 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि कई कर्मचारी आग की लपटों में फंस गए। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरातफरी मच गई।

चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने तत्काल संयुक्त राहत एवं बचाव दल घटनास्थल पर भेजे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए व्यापक जांच के आदेश दिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग फैक्ट्री के भूतल से शुरू हुई और जूता निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री तथा रसायनों के कारण कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई। सीढ़ियों पर रखा सामान भी बचाव कार्य में बड़ी बाधा बना।स्थानीय प्रशासन ने फैक्ट्री के मालिक और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है तथा कंपनी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हादसे के कारणों की विस्तृत जांच जारी है।जिनजियांग को चीन की जूता राजधानी माना जाता है और यहां बड़ी संख्या में जूता एवं परिधान निर्माण इकाइयां संचालित होती हैं। इस हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

योगी का सपा-कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा 'प्रहार'

हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज व रामभक्तों पर गोलीकांड पर बरसे योगी आदित्यनाथ

वक्फ और विकास परियोजनाओं पर विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया

432 करोड़ रुपये की 217 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया

» बीपीएस न्यूज

अयोध्या। रामनगरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा राजनीतिक हमला बोला। 432 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज आस्था और संविधान की बातें करते हैं, वही कभी अयोध्या की पवित्रता से खिलवाड़ करने का पाप कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं दलों के शासनकाल में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई थी, जिसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान माना गया।मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि देश की जनता को यह याद रखना चाहिए कि जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी कीं और सनातन आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास किया, वही आज धार्मिक सौहार्द और आस्था की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराना संभव नहीं है तो फिर अयोध्या के पवित्र धार्मिक स्थल पर नमाज पढ़वाने की अनुमति क्यों दी गई थी। उन्होंने इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ÷तुष्टिकरण की राजनीति÷ का परिणाम बताया।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समय बदल चुका है और अब अयोध्या की पहचान विवादों से नहीं, बल्कि विकास, विरासत और विश्वस्तरीय सुविधाओं से हो रही है। उन्होंने कहा कि कभी जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, एयरपोर्ट का विरोध किया और अयोध्या के विकास को रोकने की कोशिश की, आज वही विकास देखकर असहज हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने संकल्प लिया तो प्रभु श्रीराम और पवनसुत हनुमान के आशीर्वाद से वह संकल्प साकार हुआ।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बना अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने एयरपोर्ट परियोजना का लगातार विरोध किया और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन डबल इंजन सरकार ने हर बाधा को पार करते हुए अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निषादराज गुह की विरासत की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने निषादराज गुह के नाम पर रैन बसेरे का निर्माण कराया, जबकि विपक्ष को इससे भी आपत्ति रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि श्रृंगवेरपुर स्थित भगवान राम और निषादराज के ऐतिहासिक मिलन स्थल को वक्फ के नाम पर कब्जाने की कोशिश की गई थी, जिसे भाजपा सरकार ने विफल कर दिया।उन्होंने कहा कि मंशा साफ हो तो विकास अपने आप गति पकड़ता है। स्पष्ट नीति और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण ही आज अयोध्या विश्व पटल पर नई पहचान बना रही है। भव्य श्रीराम मंदिर, आधुनिक आधारभूत संरचना, चौड़ी सड़कें, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और तीर्थ पर्यटन की नई सुविधाएं इस परिवर्तन की गवाही दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर को असंभव बताते थे, आज वही उसकी भव्यता देखकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने केवल धार्मिक आस्था का सम्मान ही नहीं किया, बल्कि अयोध्या को आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने जनता से विकास और सांस्कृतिक विरासत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया।

हनुमानगढ़ी का मुद्दा क्यों बना बड़ा राजनीतिक हथियार?

मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने के पुराने विवाद को उठाकर विपक्ष पर ÷आस्था के अपमान÷ का आरोप लगाया। इससे धार्मिक पहचान और राजनीतिक विमर्श दोनों को नया केंद्र मिल गया।

राम मंदिर से विकास तक का राजनीतिक संदेश

भाजपा अयोध्या को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि विकास मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत कर रही है। एयरपोर्ट, सड़क, पर्यटन और आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं को इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।

मायावती ने साधा निशाना, पीड़ितों की आड़ में राजनीति बंद हो

» बीपीएस न्यूज

मेरठ-सहारनपुर की घटनाओं पर बोलीं- कुछ संगठन माहौल बिगाड़कर राजनीतिक लाभ लेने में जुटे

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने मेरठ और सहारनपुर की हालिया घटनाओं को लेकर राजनीतिक दलों और कुछ संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पीड़ित परिवारों की भावनाओं को भड़काकर प्रदेश का माहौल खराब करने और उससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी संगठन या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है।मायावती ने कहा कि पहले लोगों को उकसाकर तनाव और अशांति का माहौल बनाया जाता है, फिर वही लोग पीड़ितों के बीच पहुंचकर सहानुभूति जताने का दिखावा करते हैं। उन्होंने इसे मगरमच्छ के आंसू करार देते हुए कहा कि ऐसी राजनीति से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, बल्कि उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं।बसपा प्रमुख ने कहा कि दुख की घड़ी में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन, चक्काजाम और राजनीतिक गतिविधियां करना

समाधान नहीं है। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि न्याय के लिए अदालतों और कानून का सहारा लेना चाहिए, न कि कानून हाथ में लेना चाहिए।

उन्होंने जनता से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील करते हुए कहा कि समाज अपनी एकजुटता और वोट की ताकत को पहचाने। स्थायी बदलाव केवल संवैधानिक प्रक्रिया और राजनीतिक भागीदारी के जरिए ही संभव है।

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, तीन प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत

» बीपीएस न्यूज

ग्रेटर नोएडा। जेवर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से तीन प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रात करीब साढ़े 10 बजे जेवर-खुर्जा मार्ग पर नीमका गांव के सामने हुआ। तीनों मजदूर धान की रोपाई का काम पूरा करने के बाद पैदल अपने ठिकाने की ओर लौट रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों मजदूर कई फीट दूर सड़क किनारे खेत में जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को जेवर स्थित कैलाश अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतकों की पहचान बिहार के अररिया जिले के निवासी करन (22), विश्वजीत (24) और मिथुन (25) के रूप में हुई है। तीनों मजदूर जीविकोपार्जन के लिए ग्रेटर नोएडा आए थे और क्षेत्र में धान की रोपाई का कार्य कर रहे थे।पुलिस के अनुसार, बुधवार देर रात काम समाप्त होने के बाद तीनों पैदल नीमका गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जेवर की दिशा से आई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि मृतकों के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि वाहन और चालक की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

कहां गई कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा? केरल हाईकोर्ट ने रद्द की पुलिस सुरक्षा

» बीपीएस न्यूज

वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर चर्चाओं में हैं। वजह है कि केरल हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को मोनालिसा को सुरक्षा देने की बात कहने वाले अपने पिछले आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में पुलिस को मोनालिसा को सुरक्षा देने की बात कही गई थी, जब उनके पति पर उनके अपहरण का आरोप लगा था।लड़की के वकील पी.एस. अनीशाद ने बताया कि पुलिस ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस को बताया कि जब उन्होंने सुरक्षा आदेश को लागू करने की कोशिश की, तो लड़की का पता नहीं चल सका। वकील अनीशाद ने कहा कि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब लड़की सुरक्षा की मांग करते हुए संपर्क करे, तो उसे सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।पुलिस सुरक्षा का हाई कोर्ट का आदेश लड़की की उस याचिका पर आया था, जिसमें उसने अपनी जान की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश देने की मांग की थी।

तृणमूल के 12 और बैंक खाते फ्रीज, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि जांच के दायरे में

» बीपीएस न्यूज

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी फंड से जुड़े बैंक खातों की जांच और तेज हो गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट से दैनिक खर्चों के संचालन को लेकर आंशिक राहत मिलने के बावजूद बिधाननगर साइबर थाना ने तृणमूल के 12 और बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगाने का निर्देश विभिन्न सरकारी और निजी बैंकों को दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पहले और दूसरे चरण में फ्रीज किए गए खातों में कुल मिलाकर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है।यह कार्रवाई तृणमूल विधायक विश्वनाथ दास की ओर से बिधाननगर साइबर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की जा रही जांच के तहत हुई है। इसी शिकायत के बाद पहले तीन बैंक खातों को फ्रीज किया गया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इन तीन खातों को फ्रीज कर दिया। इसके खिलाफ तृणमूल ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को हाई कोर्ट ने पार्टी के नियमित खर्चों के संचालन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था।पुलिस अब पहले फ्रीज किए गए तीन खातों के लेनदेन से मिले सुरागों के आधार पर अन्य खातों की भी जांच कर रही है। इसी कारण जांच पूरी होने तक इन खातों से किसी भी प्रकार के लेनदेन पर रोक लगाई गई है।

जांच के दौरान बिधाननगर साइबर थाना शिकायतकर्ता विधायक

सहित ऋ्रब्रत गुट के सात से अधिक विधायकों के बयान दर्ज कर चुका है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि उन्हें किन आधारों पर पार्टी के खातों में कथित अवैध लेनदेन की आशंका हुई।

उधर, ईडी की जांच में भी नए तथ्य सामने आए हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, जिन तीन खातों को ईडी ने फ्रीज किया है, उनमें से एक खाते के हस्ताक्षरकर्ता दो वर्तमान सांसद हैं। वहीं, दो अन्य खातों के हस्ताक्षरकर्ता एक पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसी जल्द ही इन नेताओं को पूछताछ के लिए तलब कर उनके बयान दर्ज कर सकती है।

मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। पुलिस और ईडी दोनों ही एजेंसियां बैंक खातों में हुए वित्तीय लेनदेन और धन के स्रोतों की विस्तृत जांच कर रही हैं। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

दतिया में बगावत: नरोत्तम का टिकट कटा तो झांसी हाईवे जाम, पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे, पार्टी छोड़ने की दी चेतावनी

» बीपीएस न्यूज

दतिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी खुलकर सामने आ गई। शुक्रवार को नाराज कार्यकर्ताओं ने दतिया-झांसी हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे करीब तीन किलोमीटर लंबा वाहनों का जाम लग गया। वहीं दतिया उपचुनाव में डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का भारी विरोध हो रहा है। दतिया से भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सरण सहित सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं पार्टी छोड़ने की चेतावनी भी दी जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेतृत्व के फैसले का विरोध करते हुए नारेबाजी की। उनका कहना था कि डॉ. नरोत्तम मिश्रा के स्थान पर घोषित किए गए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को वे नहीं जानते और इस फैसले से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पार्टी में भूचाल आ गया है। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पार्टी के शीर्ष से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों ने पदों से इस्तीफे के बाद पार्टी छोड़ने तक की चेतावनी दे दी है। उनका साफ कहना है कि 24 घंटे में डॉ. नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो सभी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे।

भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र लिखा है और साथ ही प्रेस बयान जारी कर कहा कि पार्टी द्वारा दतिया उपचुनाव में लिया गया निर्णय एकतरफा है। इसमें जमीनी कार्यकर्ताओं की भावनाओं और सुझावों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर 24 घंटे के भीतर आलाकमान ने डॉ. नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी घोषित नहीं किया तो वे और उनके साथ सैकड़ों पदाधिकारी पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे देंगे। जरूरत पड़ी तो प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी जाएगी। जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा देने वालों की लंबी सूची भी जारी की। इसमें जिला अध्यक्ष सहित सभी जिला पदाधिकारी,जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष,नगर पालिका दतिया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,बड़ौनी पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,दतिया विधानसभा के 6 मंडलों के अध्यक्ष,सभी मोर्चा अध्यक्ष,दतिया और बड़ौनी के सभी पार्षदगण और दतिया विधानसभा की 291 बूथों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी शामिल है।

रघुवीर सिंह कुशवाहा ने कहा कि हम सब सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। डॉ. नरोत्तम मिश्रा ही दतिया की पहचान हैं। उनके बिना चुनाव लड़ना संभव नहीं। टिकट घोषणा के बाद से दतिया में विरोध लगातार तेज हो रहा है। पहले कार्यकर्ताओं ने झांसी हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगाया। अब संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा ने दशकों तक दतिया को सींचा है। उनके नाम पर ही भाजपा यहां मजबूत हुई।

यूपी का धन कुबेर- 60 सेकंड में गाड़ियों की फिटनेस, हर लाइसेंस पर 500 की घूस

» बीपीएस न्यूज

कानपुर ।कानपुर के गांधीनगर इलाके की सामाजिक संस्था ने इस महाभ्रष्टाचार की परतों को खोलते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसने सरकारी सिस्टम की साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। संस्था के पदाधिकारियों ने सेवानिवृत्त एआरटीओ ललित कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग और परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं।संस्था के प्रदेश अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव, महामंत्री शैलेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता ने सितंबर 2020 में %घूस को घूसा% अभियान के तहत इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। आरोप है कि ललित कुमार ने साल 2016 से 2019 के बीच कानपुर आरटीओ में संभागीय निरीक्षक के पद पर रहते हुए हर महीने करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की। इसके बाद साल 2019 में हुए उनके प्रमोशन पर भी संस्था ने कड़ी आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।संस्था की ओर से की गई शिकायत के मुताबिक, कोरोना काल से पहले आरटीओ में नए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का एक तय रेट कार्ड चलता था। उस दौरान हर दिन करीब 300 आवेदकों का स्लॉट बुक होता था। हैरानी की बात यह है कि इन 300 लोगों में से केवल 10 से 15 फीसदी लोग ही मैदान पर आकर गाड़ी चलाने का वास्तविक ट्रायल देते थे।बाकी बचे 85 से 90 फीसदी आवेदकों को बिना किसी टेस्ट और नियमों को ताक पर रखकर, प्रति लाइसेंस 500 रुपये की सीधी रिश्वत लेकर पास कर दिया जाता था। इस धन कुबेर की चालाकी और लापरवाही का सबसे बड़ा खेल वाहन फिटनेस के नाम पर खेला गया। संस्था के पदाधिकारियों ने दस्तावेजों के साथ आरोप लगाया है कि फिटनेस पॉइंट पर गाड़ियों की तकनीकी जांच के नाम पर महज खानापूर्ति होती थी। आरटीओ दफ्तर में सिर्फ 60 मिनट के भीतर 100 से अधिक वाहनों की जांच पूरी कर ली जाती थी।गणित के हिसाब से देखें तो एक वाहन की फिटनेस जांचने में 60 सेकेंड से भी कम का समय लिया जाता था। इतना ही नहीं, दलालों के सिंडिकेट के जरिए जो गाड़ियां शहर से बाहर होती थीं या आरटीओ दफ्तर तक नहीं आ पाती थीं, मोटी घूस लेकर उनका भी घर बैठे फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता था।महज 500-500 रुपये की फुटकर रिश्वत और फिटनेस के नाम पर लाखों के इस खेल ने ललित कुमार को यूपी परिवहन विभाग का सबसे बड़ा धन कुबेर बना दिया। जांच एजेंसियों द्वारा अब तक की गई.

राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 20 कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा, जांच के बीच बढ़ा काम का दबाव

» बीपीएस न्यूज

लखनऊ। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 20 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। जांच के बाद कार्यप्रणाली में बदलाव, बढ़े कार्यभार और सुरक्षा नियमों को इसकी वजह बताया जा रहा है। अब सीमित कर्मचारियों के साथ गिनती का काम चल रहा है और नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी जारी है।

राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 20 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार, चढ़ावे में कथित गबन की जांच शुरू होने के बाद कार्य का दबाव बढ़ने और बदली कार्यप्रणाली के चलते कर्मचारियों ने यह फैसला लिया। इस्तीफों के बाद अब गिनती केंद्र में केवल करीब एक दर्जन कर्मचारी ही नियमित रूप से काम कर रहे हैं।

ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक, गबन का मामला सामने आने के बाद ही कर्मचारियों की उपस्थिति कम होने लगी थी। पहले जहां करीब 40 कर्मचारी इस कार्य में लगे थे, वहीं जांच के बाद केवल 15 से 20 कर्मचारी ही नियमित रूप से ड्यूटी पर आ रहे थे। अब इनमें से करीब 20 कर्मचारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है।

कर्मचारियों का कहना है कि पहले चढ़ावे की गिनती दो शिफ्टों में होती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया एक ही शिफ्ट में करीब नौ से दस घंटे तक चलती है। इसके बावजूद मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने यह भी बताया कि पहले टेबल-कुर्सियों पर बैठकर गिनती होती थी, जबकि अब फर्श पर बैठकर काम कराया जा रहा है।

जांच के बाद गिनती केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी सख्त कर दी गई है। कर्मचारियों को कई चरणों की तलाशी के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। उन्हें बिना जूते-चप्पल, मोबाइल फोन और निजी सामान के ही अंदर जाने की अनुमति है। मंदिर परिसर में विभिन्न सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही वे गिनती केंद्र तक पहुंचते हैं।

सूत्रों के अनुसार, गिनती प्रक्रिया की निगरानी के लिए चार कर्मचारियों की अलग से तैनाती की गई है। ट्रस्ट क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक समान यूनिफॉर्म और डिजिटल एंट्री-एग्जिट सिस्टम लागू करने की तैयारी भी कर रहा है। वहीं, चढ़ावे में कथित गबन मामले में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस जांच के साथ ट्रस्ट की आंतरिक जांच भी जारी है।

क्या आप की हड्डियों में हो रही है 'कट-कट' की आवाज

जाने कब है नॉर्मल और कब है खतरे की घंटी?

आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की समस्याएं बढ़ती हैं। लेकिन अब कम उम्र में भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह खराब लाइफस्टाइल और पोषक तत्वों की गड़बड़ी है। अगर आपको भी उठने-बैठने के दौरान हड्डियों के चटकने की कट-कट आवाज आती है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आमतौर पर माना जाता है कि कट-कट की आवाज का मतलब हड्डियां घिस रही हैं, लेकिन हर चटकने वाली आवाज की यही वजह हो ऐसा जरूरी नहीं है। शरीर-रचनाविज्ञान

कई बार यह जोड़ों के अंदर मौजूद गैस के बुलबुलों के फूटने, लिंगामेंट और टेंडन के अपनी जगह बदलने या फिर लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से यह समस्या होती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक अगर सिर्फ चटकने की आवाज आ रही है, तो यह बहुत गंभीर समस्या नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ सूजन, दर्द, जकड़न, चलने-फिरने में समस्या या फिर जोड़ बार-बार लॉक हो रहे हैं। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए।

हड्डियों की दिक्कतें

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक लोगों की खराब हो रही लाइफस्टाइल जैसे घंटों तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, फिजिकल एक्टिविटी में कमी होना और मोटापे की समस्या ने हड्डियों की समस्या को काफी हद तक बढ़ा दिया है।वहीं विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का भी हड्डियों और जोड़ों पर असर होता है।उम्र बढ़ने के अलावा शरीर में होने वाले बदलाव भी जोड़ों की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं।हड्डियों या जोड़ों से क्यों आती है चटखने की आवाजहेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक जोड़ों से आने वाली चटकने की आवाज को मेडिकल भाषा में क्रेपिटस कहा जाता है। आमतौर पर यह सामान्य मानी जाती है।जोड़ों के अंदर मौजूद सिनोवियल फ्लूइड में घुली गैसें दबाव के बदलने पर छोटे बुलबुले बनाती और फूटती है। जिससे यह चटकने की आवाज आती है।वहीं टेंडन या लिगामेंट का हड्डी के ऊपर से खिसकने से भी ऐसी आवाजें पैदा कर सकता है।

अगर चटकने की आवाज बिना दर्द या सूजन के आती है, तो इसको चिंता नहीं मानी जाती है।

किन लोगों को ज्यादा खतरा

आमतौर पर कार्टिलेज का घिसाव उम्र बढ़ने के साथ बढ़ सकता है। इसलिए बुजुर्गों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है।वहीं वेट ज्यादा होने से भी कूल्हों और घुटनों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है।फिजिकल एक्टिविटी में कमी, लंबे समय तक बैठे रहने वालों में या फिर घुटनों पर चोट की वजह भी आपको कई दिक्कतें हो सकती हैं।महिलाओं में मेनोपॉज होने के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव से भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जिससे कट-कट की आवाज आ सकती हैं।

ऐसे करें बचाव

एक्सपर्ट के मुताबिक अगर हड्डियों के चटकने के साथ-साथ सूजन, तेज दर्द या जोड़ गर्म महसूस होते हैं। या फिर बार-बार लॉक होने की वजह से चलने में समस्या हो रही है, तो इसकी जांच जरूर कराएं। शरीर-रचनाविज्ञानवहीं नियमित व्यायाम और फिजिकट एक्टिविटी से जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है।वेट कंट्रोल में रखने से कूल्हों और घुटनों पर अनावश्यक भार कम होता है।वहीं संतुलित डाइट लेनी चाहिए। अपनी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी वाली चीजों को शामिल करें। इससे हड्डियां मजबूत होती है।

क्या आपको पता है जहर घोल रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स

बढ़ा रहे हार्ट अटैक का खतरा

अधिकतर लोग सुबह नाश्ते में पैकेज्ड ब्रेड, शाम को नूडल्स और ऑफिस में बिस्किट या चिप्स खाते हैं। अगर यह आपकी भी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो सतर्क होने का समय है। क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि कई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में ज्यादा चीनी, नमक, अनहेल्दी फैट, प्रिजर्वेटिव्स और कृत्रिम रंग मिलाए जाते हैं। जो आपके शरीर पर लंबे समय तक निगेटिव असर डाल सकते हैं।

समयऔर कैलेंडर

कई लोग बिना जाने-समझे हर रोज ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। धीरे-धीरे यह आदत हाई बीपी, मोटापा, हृदय संबंधी बीमारी, टाइप-2 डायबिटीज और पाचन से जुड़ी परेशानियों के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। वहीं कुछ शोधों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन करने से मेंटल हेल्थ और पूरे शरीर के लिए खतरनाक साबित होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप सिर्फ डाइट को सही कर लें, तो कई तरह की बीमारियों के खतरे से खुद को बचा सकते हैं।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स तो नहीं खा रहे आप

इसको तैयार करने में कई रासायनिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड में प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का अंश बहुत कम या न के बराबर होता है। इनको स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए ज्यादा चीनी, नमक, अनहैल्दी फैट और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं।

इस तरह के खाद्य पदार्थों में कई तरह के फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन इनमें प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व नहीं होते हैं। जिससे आपके शरीर को फायदे की जगह नुकसान होता है।एक्सपर्ट की मानें, तो इन चीजों को कोलेस्ट्रॉल और वजन की समस्या बढ़ाने वाला माना जाता है। यह दोनों ही शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। इससे वेट तेजी से बढ़ सकता है।

जानें क्या कहते हैं शोधकर्ता

एक स्टडी के मुताबिक पुरुषों को रोजाना 36 ग्राम से ज्यादा मात्रा में नमक या चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए यह मात्रा 25 ग्राम निर्धारित है। वहीं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में चीनी और नमक दोनों की मात्रा ज्यादा होती है। व्हाइट ब्रेड, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड क्रेकर्स आदि चीजों का ज्यादा सेवन शरीर के लिए कई तरह से नुकसानदायक हो सकता है। इन चीजों का ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर के लिए कई तरह से हानिकारक हो सकता है।

ज्यादा न करें ब्रेड का सेवन

खासतौर पर व्हाइट ब्रेड हमारी सेहत के लिए कई तरह से नुकसानदायक हो सकता है। पैकेज्ड ब्रेड में स्टार्च और मैदे की मात्रा ज्यादा होती है। जिसकी वजह से न सिर्फ पाचन की दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं यह डायबिटीज रोगियों के लिए भी नुकसानदेह हो जाता है। पैकेज्ड कोल्ड मीट में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होते हैं। फ्रेंच फ्राइज, आइस्क्रीम और कुकीज का सेवन भी शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

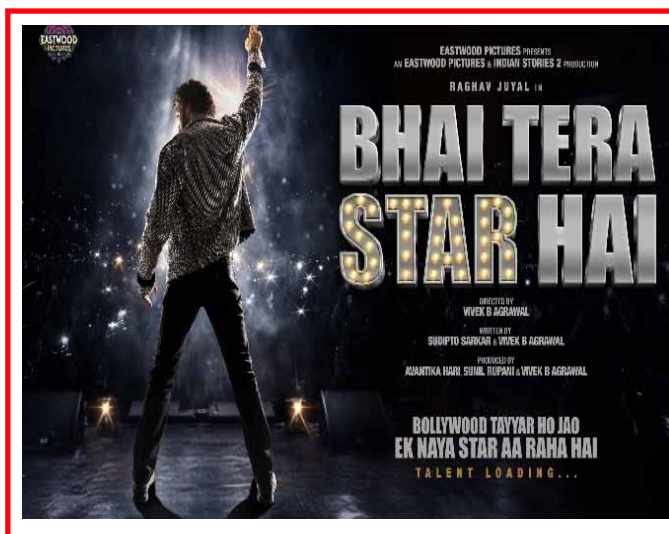

विवेक बी. अग्रवाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का फर्स्ट लुक जारी..!

ईस्टवुड पिक्चर्स तथा इंडियन स्टोरीज़ 2 के संयुक्त तत्वाधान में निर्मित फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है, जिसके साथ फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। पोस्टर में अजय सिंह नज़र आ रहे हैं और उस पर लिखा है यह पोस्टर एक ऐसे युवा की झलक दिखाता है, जिसके हौसले आसमान छूते हैं, सपने बेहद बड़े हैं और जो खुद को किसी स्टार से कम नहीं मानता।

लेकिन आखिर अजय सिंह कौन है? क्या वह सच में स्टार बनने की राह पर है या फिर उसे पहले से ही पूरा यकीन है कि वह स्टार है? इसका जवाब फिलहाल मेकर्स ने राज़ ही रखा है।

लंदन की खूबसूरत पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म युवाओं की ऊर्जा, हल्के-फुल्के हास्य, यादगार किरदारों और शानदार संगीत से भरपूर मनोरंजन का वादा करती है। पहला पोस्टर सिर्फ अजय सिंह की दुनिया की एक झलक है। आने वाले दिनों में मेकर्स फिल्म से जुड़े कई नए खुलासे, इवेंट्स, गाने और सरप्राइज़ दर्शकों के सामने लाने वाले हैं। 'भाई तेरा स्टार है' का निर्देशन विवेक बी. अग्रवाल ने किया है। फिल्म की कहानी और पटकथा सुदीप्तो सरकार और विवेक बी. अग्रवाल ने लिखी है। फिल्म का निर्माण अवंतिका हरी, सुनील रूपाणी और विवेक बी. अग्रवाल ने किया है।

प्रस्तुति-काली दास पाण्डेय

थाईलैंड में हरियाणा के धीरज कुमार का दम

एशियन चैंपियनशिप में जीता कांस्य

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के छात्र धीरज मलिक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लहराया भारत का परचम, एशियन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के छात्र धीरज कुमार मलिक ने अपनी शानदार खेल प्रतिभा का परिचय देते हुए थाईलैंड के पटाया में आयोजित जूनियर एशियन ग्रीको-रोमन कुश्ती चैंपियनशिप-2026 के 77 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत, हरियाणा और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय परिसर में खुशी और गर्व का माहौल है।

धीरज मलिक ने कठिन मुकाबलों का सामना करते हुए अपने उत्कृष्ट तकनीकी कौशल, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया। एशियाई स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतना न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि भारतीय कुश्ती और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय की खेल परंपरा के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। धीरज की उपलब्धियों का सिलसिला लगातार जारी है। वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता के 77 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। जनवरी 2026 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित एआईआईयू इंटर यूनिवर्सिटी कुश्ती प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक जीतकर विश्वविद्यालय की झोली में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ी।

इससे पूर्व वर्ष 2025 में आयोजित सीनियर हरियाणा राज्य कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का परिचय दिया। धीरज का खेल सफर प्रारंभ से ही उल्लेखनीय रहा है। वर्ष 2024 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित स्कूल नेशनल प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक जीता, जबकि वर्ष 2023 में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित स्कूल नेशनल प्रतियोगिता तथा गोंडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित कैडेट नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की। धीरज मलिक के पिता कृष्ण कुमार जिला जींद के गांव निडाना निवासी ने अपने पुत्र की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे परिवार और क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया।

इस अवसर पर बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी ने धीरज मलिक को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेल एवं अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि धीरज की यह उपलब्धि देशभर के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और यह सिद्ध करती है कि समर्पण, अनुशासन एवं निरंतर मेहनत से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि धीरज भविष्य में विश्व स्तर पर भी भारत का गौरव बढ़ाएंगे।

कुलपति प्रो. (डॉ.) बी. एम. यादव ने कहा कि बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्कृष्ट खेल सुविधाएं एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। धीरज की सफलता विश्वविद्यालय की खेल संस्कृति, प्रशिक्षकों की मेहनत और विद्यार्थियों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय भविष्य में भी खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग प्रदान करता रहेगा।

कुलसचिव (रजिस्ट्रार) डॉ. विनोद कुमार ने धीरज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से पूरे विश्वविद्यालय परिवार का गौरव बढ़ा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि धीरज आने वाले राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय और देश का नाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

खेल निदेशक डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि धीरज मलिक अत्यंत अनुशासित, मेहनती एवं समर्पित खिलाड़ी हैं। उनकी निरंतर अभ्यास करने की आदत और जीत का जज्बा ही उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो संस्थान की मजबूत खेल व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का प्रमाण है।

धीरज मलिक की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि धीरज भविष्य में भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का तिरंगा शान से लहराते हुए बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, हरियाणा और देश का नाम विश्व पटल पर और अधिक गौरवान्वित करेंगे।

केस्को की संवेदनहीनता: हेल्पलाइन 1912 फेल, गल्ला मंडी सब-स्टेशन पर रातभर उपभोक्ताओं का हंगामा

नौबस्ता सागर पुरी में 24 घंटे गुल रही बत्ती, अफसरों ने मोबाइल किए स्विच ऑफ पीड़ितों का गंभीर आरोप: 'सुविधा शुल्क देने वालों का काम होता है पहले'

बीपीएस न्यूज-विशेष संवाददाता

कानपुर, गल्ला मंडी। स्मार्ट सिटी कानपुर में निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के सागर पुरी इलाके में केस्को की बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता का एक संगीन मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक घरेलू उपभोक्ता को खंभे से खराब बिजली सही कराने में पूरे 24 घंटे तक विभागीय दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। भीषण उमस और गर्मी के बीच बच्चे पानी और दैनिक कार्यों के लिए तरस गए, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोते रहे। आक्रोशित उपभोक्ताओं का आरोप है कि सब-स्टेशन में भारी मनमानी व्याप्त है और जो 'सुविधा शुल्क' देता है, उसकी सुनवाई पहले की जाती है।

24 घंटे की प्रताड़ना- 1912 से लेकर अफसरों तक सिर्फ आश्वासन

पीड़ित उपभोक्ता के अनुसार, रात करीब 2:00 बजे बिजली के पोल में कार्बन आ जाने से उनके घर की लाइन में तकनीकी खराबी आ गई थी।

सुबह जानकारी होने पर पीड़ित ने सुबह 11:00 बजे केस्को की मुख्य हेल्पलाइन 1912 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने करीब 10 किलोमीटर दूर मंडी समिति सब-स्टेशन जाकर वहां तैनात एसएसओ को भी व्यक्तिगत रूप से समस्या से अवगत कराया।

दोपहर 3:15 बजे तक जब कोई लाइनमैन नहीं पहुंचा, तो पीड़ित ने दोबारा 1912 और केस्को कार्यालय में कई बार फोन कर गुहार लगाई। शाम 4:15 बजे तीसरी बार शिकायत करने पर हेल्पलाइन द्वारा समस्या का निवारण करने के बजाय जेई (8189045191) और एसएसओ (8189045193) के सरकारी नंबर थमा दिए गए। आरोप है कि जब इन नंबरों पर संपर्क किया गया तो जेई का फोन नेटवर्क से बाहर था और एसएसओ/लाइनमैन का मोबाइल स्विच ऑफ मिला।

आधी रात को फूटा गुस्सा, सब-स्टेशन का घेराव

घर में पानी की बूंद-बूंद को तरसते बच्चों की परेशानी देख पीड़ित उपभोक्ता रात करीब 11:30 बजे गल्ला मंडी सब-स्टेशन पहुंचे। वहां का नजारा देख वे दंग रह गए। सब-स्टेशन पर पहले से ही दर्जनों आक्रोशित उपभोक्ता अपनी-अपनी शिकायतें लेकर धरने पर बैठे थे और विभागीय कर्मचारियों से उनकी तीखी नोकझोंक चल रही थी।

उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि सब-स्टेशन के कर्मचारियों ने शाम से ही सरकारी मोबाइल फोन जानबूझकर स्विच ऑफ कर रखा था ताकि जनता की शिकायतें न सुननी पड़ें। जब लोगों ने सब-स्टेशन का घेराव किया और हंगामा बढ़ा, तब जाकर आनन-फानन में मोबाइल चालू किया गया।

केस्को एमडी से होगी लिखित शिकायत

देर रात 1:00 बजे तक सब-स्टेशन पर

उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जमा रही और नारेबाजी होती रही। स्थानीय नागरिकों ने केस्को के इस तानाशाही रवैए और लापरवाही के खिलाफ सीधे प्रबंध निदेशक से लिखित शिकायत करने का निर्णय लिया है। इस दौरान मुख्य रूप से पीड़ित दिलीप कुमार मिश्रा, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, जितेंद्र मिश्रा, अवधेश भदौरिया, कुंवर पाल, मुन्ना शुक्ला, मोनू रावत सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे।

बीपीएस न्यूज़ का सवाल- सरकारी CUG नंबर आखिर क्यों रहते हैं बंद?

जनता का सीधा सवाल है कि केस्को द्वारा जो आधिकारिक नंबर बिजली संकट के समय त्वरित निवारण के लिए जारी किए जाते हैं,

वे संकट के समय अक्सर बंद या नॉट रीचेबल क्यों हो जाते हैं?

अगर अधिकारी फोन पर ही सही स्थिति स्पष्ट कर दें, तो आधी रात को जनता को सब-स्टेशनों पर जाकर हंगामा न करना पड़े। क्या ऐसे गैर-जिम्मेदार कर्मचारियों पर केस्को प्रबंधन कोई सख्त कार्रवाई करेगा?

24 घंटे की भूख हड़ताल एवं अनशन का हुआ समापन

बीपीएस न्यूज

कानपुर। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (स्स्रढ्ढ), कानपुर जिला कमेटी द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं, छात्र अधिकारों तथा कानपुर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में व्याप्त छात्र समस्याओं को लेकर आयोजित 24 घंटे की भूख हड़ताल एवं अनशन का शुक्रवार को विभिन्न जनसंगठनों के समर्थन और एकजुटता के बीच समापन हुआ।

इस अनशन में जिला संयोजक महबूब आलम, विधि छात्र एसएफ़आई उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य एवं एसएफ़आई कानपुर जिला सहसंयोजक आराध्य बाजपेयी, जुनैद मंसूरी तथा अश्वनी मिश्रा अनशन पर बैठे। अनशन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा का बढ़ता निजीकरण, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताएँ, पेपर लीक, युवाओं में बढ़ती बेरोज़गारी तथा छात्रों की अनदेखी देश की शिक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती हैं। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने की भी मांग उठाई। कार्यक्रम में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, जनवादी महिला समिति, जनवादी नौजवान सभा, दलित शोषण मुक्ति मंच, सद्भावना समिति कानपुर सहित विभिन्न जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों और शिक्षा बचाने की लड़ाई का महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों और युवाओं की न्यायसंगत आवाज़ को दबाने के बजाय उसे गंभीरता से सुनना और उसके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है। भूख हड़ताल का समापन सीटू (ष्टढ्ढञ्ज) के जिला कोषाध्यक्ष कॉमरेड मोहम्मद वसी ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर कराया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एसएफ़आई ने शिक्षा और छात्र अधिकारों के सवालों को मजबूती से उठाया है तथा भविष्य में भी संगठन जनहित और छात्रहित के मुद्दों पर और व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा करेगा। एसएफ़आई कानपुर ने स्पष्ट किया कि 24 घंटे की भूख हड़ताल आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, समान अवसर और छात्र अधिकारों की लड़ाई को और व्यापक रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प है। संगठन ने कहा कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक लोकतांत्रिक संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड 77 पार्षद ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन

बीपीएस न्यूज

कानपुर। बर्रा वार्ड 77 पार्षद डॉ अखिलेश बाजपेयी के द्वारा बर्रा 2 स्थित सचान चौराहा से मोगली स्वीट हाउस तक फुटपाथ इंटर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर पार्षद डॉ अखिलेश बाजपेयी ने बताया कि नगर महापौर एवं नगर निगम के सहयोग से निरन्तर वार्ड के सम्पूर्ण कार्यों का कार्य तेजी से हो रहा है। इस दौरान पार्षद बाजपेयी ने क्षेत्रीय महिलाओं एवं माताओं से हालचाल लेते हुए समस्याओं के बारे में जानकारी ली।

क्षेत्रीय सुमित मिश्रा ने कहा कि मौजूदा पार्षद के द्वारा निरन्तर क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण कराया जा रहा हैं। भूमि पूजन वरिष्ठ समाजसेवी एवं संरक्षक पार्षद वेलफेयर अमित पाण्डेय बंटी के द्वारा किया गया। पूजन के उपरांत क्षेत्रीय वरिष्ठ जनो का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया।

इस मौके पर मुख्य रूप से पार्षद नीरज गुप्ता पार्षद, गुंजन शर्मा पार्षद, अनुराग शुक्ला पार्षद, मनीष मिश्रा आचार्य पंडित सुधीर मिश्रा, पंडित गिरधारी लाल मिश्रा, राम जी शुक्ला, रामू सचान, सुनील त्रिवेदी, जीतू त्रिपाठी, प्रखर शुक्ला, आनंद बाजपेई, अजय त्रिपाठी, विपिन त्रिवेदी, कृष्ण अवस्थी, विनोद अवस्थी, गोलू मिश्रा, राघव शुक्ला, अनिल सैनी, लल्ला यादव सहित काफी संख्या में क्षेत्रीय मौजूद रहे।

कानपुर कचहरी में वकील-कांस्टेबल में सरेआम जमकर हुई मारपीट

बीपीएस न्यूज

कानपुर। कानपुर कचहरी में वकील-कांस्टेबल के बीच मारपीट हो गई। अधिवक्ता और पुलिस कांस्टेबल के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीसीपी ईस्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। प्राथमिक जांच में एक कांस्टेबल पहले से निलंबित और गैरहाजिर मिला, जबकि दूसरे कांस्टेबल को अनुशासनहीनता और नशे की हालत में विवाद करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सीएसए परिसर से निकली पौध बारात, जनप्रतिनिधियों और बच्चों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

प्रत्येक परिवार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए और उसका संरक्षण करें : राकेश सचान

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। प्रदेशव्यापी वृहद वृक्षारोपण महाअभियान-2026 के अंतर्गत रविवार को जनपद कानपुर नगर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में जिला स्तरीय वृक्षारोपण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान तथा विशिष्ट अतिथि सांसद रमेश अवस्थी ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं वनावरण संवर्धन का संदेश दिया। कार्यक्रम में महापौर प्रमिला पांडेय, विधायक नीलिमा कटियार, विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक एवं सलिल बिश्नोई तथा जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित सहित जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की।कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं तथा वन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में सफल विद्यार्थियों एवं वन महोत्सव में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों की अगुवाई में गाजे-बाजे के साथ आकर्षक पौध बारात निकाली गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, युवाओं एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।प्रदेश शासन द्वारा नामित जनपद के नोडल अधिकारी एवं प्रमुख सचिव (श्रम एवं सेवायोजन) डॉ. एम.के. शनमुगा सुंदरम, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता तथा मुख्य वन संरक्षक कानपुर मंडल एन.के. जानू की अगुवाई में जिला प्रशासन एवं वन विभाग ने कार्यक्रम का सफल आयोजन कराया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, प्रभागीय वन अधिकारी आकांक्षा जैन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी पौधरोपण किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, शिक्षकों एवं युवाओं की विशेष भागीदारी रही।विश्वविद्यालय स्थित योग वाटिका में पीपल, कदंब, गुलमोहर, कचनार, आंवला, अमरूद, जामुन, नीम एवं महोगनी सहित विभिन्न फलदार, पुष्पदार एवं छायादार प्रजातियों के पौधे रोपे गए। योग वाटिका से सटे मैदान में स्कूली बच्चों एवं गंगा टास्क फोर्स द्वारा 500 पौधों का रोपण किया गया।मुख्य अतिथि राकेश सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कानपुर में इस महाअभियान की शुरुआत सीएसए परिसर से हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों से वृक्षारोपण अभियान निरंतर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ÷एक पेड़ माँ के नाम÷ अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए और उसके संरक्षण का दायित्व भी निभाए। उन्होंने कहा कि सरकार निःशुल्क पौधे उपलब्ध करा रही है तथा पौधों के संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं।

प्रदेश शासन द्वारा नामित जनपद के नोडल अधिकारी डॉ. एम.के. शनमुगा सुंदरम ने कहा कि कानपुर नगर में 40 लाख से अधिक पौधों का रोपण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान की वास्तविक सफलता पौधों के संरक्षण और उनकी नियमित देखभाल में निहित है। जनपद में लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक नागरिक यदि लगाए गए पौधे की नियमित देखभाल का संकल्प ले, तो कानपुर को और अधिक हरित एवं पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध बनाया जा सकता है।प्रभागीय वन अधिकारी आकांक्षा जैन ने बताया कि जनपद में वन विभाग द्वारा 8,90,000 तथा विभिन्न अन्य विभागों द्वारा 28,73,200 पौधों का रोपण किया गया। इस प्रकार जनपद में कुल 37,63,200 पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण एवं नियमित देखभाल पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

पीड़ित महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर से मिल रही 'मुफ्त कानूनी सलाह' और 'साइबर फ्रॉड से सुरक्षा'

बीपीएस न्यूज़, विशेष जागरूकता अभियान

आधुनिक समाज में जहां एक ओर तकनीक और जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के स्वरूप भी बदल रहे हैं। घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के साथ-साथ आज के डिजिटल युग में महिलाएं 'साइबर फ्रॉड' और 'ऑनलाइन हैरेसमेंट' का भी तेजी से शिकार हो रही हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, मुसीबत में फंसी किसी भी महिला के लिए सरकार द्वारा संचालित 'वन स्टॉप सेंटर' (सखी) एक मजबूत ढाल और उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है।

'वन स्टॉप सेंटर' पीड़ित महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और डिजिटल दुनिया में साइबर ठगी या ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई महिलाओं को संकट से बाहर निकालता है।

1. कानूनी उलझनों से मुक्ति- बिना किसी खर्च के न्याय की गारंटी

अक्सर देखा जाता है कि हिंसा या प्रताड़ना का शिकार होने के बाद भी कई महिलाएं कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहतीं, क्योंकि उनके पास वकीलों की भारी-भरकम फीस देने के पैसे नहीं होते। वन स्टॉप सेंटर इसी मजबूरी को खत्म करता है।

पैनल वकीलों की मुफ्त सेवा- सेंटर में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से संबद्ध अनुभवी वकील तैनात होते हैं। ये वकील पीड़ित महिला से बिना एक भी रुपया लिए उसकी पूरी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं।

केस दर्ज कराने में मदद- पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने से लेकर कोर्ट में अर्जी लगाने तक, हर कानूनी प्रक्रिया में सेंटर के विशेषज्ञ महिला के साथ खड़े रहते हैं।

अधिकारों के प्रति जागरूकता- कानूनी भाषा और धाराओं को सरल शब्दों में समझाकर पीड़ित महिला को उसके अधिकारों (जैसे- भरण-पोषण, घरेलू हिंसा से संरक्षण आदि) के प्रति जागरूक किया जाता है।

राहत की बात- महिला को न्याय पाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने या कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सेंटर उसकी पूरी कानूनी जिम्मेदारी खुद उठाता है।

डिजिटल युग का नया खतरा-साइबर फ्रॉड से ऐसे बचाता है सेंटर

आजकल लोन ऐप के जरिए ब्लैकमेलिंग, सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर बदनाम करना, डीपफेक, और बैंक खातों से ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। लोक-लाज और बदनामी के डर से महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं।

वन स्टॉप सेंटर ऐसी स्थिति में एक सुरक्षित कवच प्रदान करता है

गोपनीयता और तुरंत एक्शन- सेंटर में आने वाली हर शिकायत को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। पीड़ित महिला की पहचान उजागर किए बिना सेंटर सीधे साइबर सेल और पुलिस प्रशासन से संपर्क कर कार्रवाई सुनिश्चित कराता है।

फर्जी कंटेंट को हटवाना- सोशल मीडिया पर अगर किसी महिला की आपत्तिजनक या मॉर्फ्ड (फर्जी) तस्वीरें/वीडियो पोस्ट की गई हैं, तो सेंटर आईटी विशेषज्ञों की मदद से उन्हें तुरंत इंटरनेट से हटवाने की प्रक्रिया शुरू करता है।

वित्तीय धोखाधड़ी में मदद- यदि कोई महिला ऑनलाइन वित्तीय ठगी का शिकार हुई है, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराकर उसके पैसे होल्ड कराने और कानूनी कार्रवाई में मदद की जाती है।

मानसिक संबल (कौंसलिंग)- साइबर अपराधों के कारण महिलाएं अत्यधिक मानसिक तनाव या डिप्रेशन में चली जाती हैं। सेंटर में मौजूद प्रोफेशनल काउंसलर्स उन्हें इस सदमे से बाहर निकालने के लिए मुफ्त मनोवैज्ञानिक परामर्श देते हैं।

हर पीड़ित महिला के लिए 'एक ही छत के नीचे' पांच बड़ी सुविधाएं

वन स्टॉप सेंटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पीड़ित महिला को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। यहाँ एक ही छत के नीचे 5 मुख्य सेवाएं मिलती हैं-

1. मुफ्त कानूनी सहायता (Legal Aid)
2. चिकित्सकीय सहायता (Medical Help)
3. अस्थायी आश्रय (5 दिनों तक रहने की सुरक्षित व्यवस्था)
4. पुलिस सहायता (Police Desk)
5. मनोवैज्ञानिक परामर्श (Counseling)

बीपीएस न्यूज़ की अपीलः-

यदि आपके आस-पास कोई भी महिला किसी भी प्रकार की हिंसा, कानूनी विवाद या साइबर अपराध से परेशान है, तो उसे डरने या चुप रहने की जरूरत नहीं है। वह तुरंत अपने नजदीकी जिला अस्पताल परिसर में स्थित वन स्टॉप सेंटर से संपर्क कर सकती है,

या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 (महिला हेल्पलाइन) पर कॉल करके मदद पा सकती है। याद रखें, आपकी सतर्कता और सही जानकारी ही किसी महिला को नया जीवन दे सकती है।

काकादेव में ज्वेलरी शॉप से 60 लाख के जेवर पार

» बीपीएस न्यूज

कानपुर। शहर के काकादेव थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। यहाँ शनिवार देर शाम एक आभूषण की दुकान से शातिर चोर ने करीब 60 लाख रुपये के गहने और नकदी पार कर दिए। इस बड़ी चोरी की खबर फैलते ही स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को एडीसीपी सेंट्रल, एसीपी स्वरूप नगर और क्राइम ब्रांच की टीमों ने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ित कारोबारी से विस्तृत पूछताछ की।

रोज आता था, भरोसा जीतकर की चोरी

विजयनगर के रहने वाले बुजुर्ग व्यापारी देवेंद्रनाथ वर्मा फल मंडी के पास %ज्योति ज्वेलर्स व वर्मा वस्त्रालय% नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। उनकी पत्नी पैरालिसिस (लकवा) से पीड़ित हैं, जिसके कारण दुकान

की पूरी जिम्मेदारी देवेंद्रनाथ अकेले ही संभालते हैं। शनिवार शाम करीब 4 बजे उन्होंने दुकान खोली। कुछ ही देर बाद वहाँ एक युवक आया। पीड़ित के मुताबिक, यह युवक चार दिन पहले कपड़े खरीदने आया था और तब से लगातार दुकान के चक्कर काट रहा था।

नजर हटते ही बैग किया गायब

शनिवार शाम करीब 5 बजे जब वह युवक दुकान में मौजूद था, तभी देवेंद्रनाथ कुछ देर के लिए बाथरूम चले गए। जब वे लौटकर आए तो वह युवक वहाँ से जा चुका था। रात करीब 9 बजे जब बुजुर्ग व्यापारी दुकान बढ़ाकर घर जाने की तैयारी करने लगे, तो उनका मुख्य बैग गायब था। काफी तलाशने के बाद भी जब बैग नहीं मिला, तो उनके होश उड़ गए।

लाखों के जेवर और नकदी ले उड़ा शातिर

पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि गायब हुए बैग में लगभग 400 ग्राम सोने के गहने, एक किलोग्राम से अधिक चांदी के आभूषण और 50 हजार रुपये की नकदी रखी हुई थी, जिसकी कुल कीमत करीब 60 लाख रुपये है।इस हाई-प्रोफाइल चोरी पर एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि शातिर चोर बड़ी चालाकी से बैग लेकर रफूचक्कर हुआ है। पुलिस दुकान और उसके आसपास लगे सीसीटीवीकैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी का सुराग लगाया जा सके। मामले के जल्द खुलासे और चोर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 विशेष टीमों को काम पर लगाया गया है।

जब औलाद ने छोड़ा साथ, तो कानून ने थामा हाथ!

सच्ची कहानी, अंक- 2

बीपीएस न्यूज़ की बुजुर्गों के अधिकारों पर विशेष सामाजिक जागरूकता मुहीम (भाग- 2)

प्रिय पाठकों, आज की आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर उन हाथों को भूल जाते हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। समाज में बुजुर्गों के साथ बढ़ती उपेक्षा और अकेलेपन को देखते हुए 'बीपीएस न्यूज़' एक नई मुहिम चला रहा है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007' की संपूर्ण जानकारी हम हर हफ्ते किस्तों में आप तक पहुँचाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल कानून बताना नहीं, बल्कि हर बुजुर्ग को उसका हक और हर नागरिक को उसका कर्तव्य याद दिलाना है। आइए, इस मुहिम से जुड़ें और जागरूक बनें।

अंक 2:-भरण-पोषण की मांग कौन और किससे कर सकता है?

अधिकार की बातः- बच्चों की कानूनी जिम्मेदारी और बुजुर्गों का हक

पिछले अंक में हमने जाना कि यह कानून क्या है। आज हम जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत कौन भरण-पोषण (खर्चा) पाने का हकदार है और किसे यह खर्चा देना होगा।

» कौन दावा कर सकता है?

कोई भी माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक जो अपनी संपत्ति या अपनी कमाई से अपना गुजारा करने में पूरी तरह असमर्थ हैं।

खर्चा देने के लिए कानूनी रूप से कौन बाध्य है?

बच्चेः- इसमें वयस्क बेटे, बेटियां, पोते और पोतियां शामिल हैं (नाबालिग बच्चे इसमें शामिल नहीं हैं)।

रिश्तेदारः- यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के कोई बच्चे नहीं हैं, तो वह ऐसे किसी भी वयस्क कानूनी वारिस या रिश्तेदार से भरण-पोषण मांग सकता है, जिसे भविष्य में उस बुजुर्ग की संपत्ति विरासत में मिलने वाली है।

याद रखेंः यदि बच्चे या रिश्तेदार सक्षम होने के बावजूद बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं, तो यह कानूनन अपराध है।

» बीपीएस न्यूज़- सच्ची कहानी

एसडीएम कोर्ट में सुलह, बेटे-बहू ने मांगी माफी, 'एसडीएम कोर्ट का आदेश बना बुजुर्गों की ढाल'

कानपुर। कहा जाता है कि बुढ़ापे में औलाद माता-पिता की लाठी बनती है, लेकिन जब वही लाठी बुजुर्गों पर बरसने लगे तो कानून ही उनका एकमात्र सहारा बनता है। ऐसा ही एक झकझोर देने वाला और बाद में राहत देने वाला मामला काकादेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आया है। जहाँ एक 66 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी पत्नी, जो कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और चलने-फिरने में भी लाचार हैं, अपने ही सगे बेटे और बहू के अत्याचारों का शिकार हो रहे थे।

बुजुर्ग दंपत्ति का आरोप था कि उनका पुत्र नशे का आदी है और बहू के साथ मिलकर लगातार मकान को अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। मना करने पर न सिर्फ सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया जाता था, बल्कि मारपीट कर जबरन घर से निकालने की धमकियाँ भी दी जा रही थीं। आए दिन होने वाली इस गाली-गलौज और हिंसा के कारण बुजुर्ग दंपत्ति अपने ही घर में जान-माल के खतरे के साए में जीने को मजबूर थे।

» जब बुजुर्ग ने उठाया कानूनी कदम

अत्याचार की पराकाष्ठा होने पर बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाई और अपने बेटे-बहू को मकान से बेदखल करने के लिए एसडीएम कोर्ट (भरण-पोषण ट्रिब्यूनल) में एक वाद दाखिल किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने इसे सुलह अधिकारी के सुपुर्द किया।

» सुलह अधिकारी की सूझबूझ से बिखरने से बचा परिवार

इस वाद की सुनवाई सुलह अधिकारी डॉ. धीरेंद्र कुमार दोहरे द्वारा की गई। उन्होंने दोनों पक्षों को बराबर तारीखों पर बुलाकर बेहद धैर्यपूर्वक सुना। सुलह अधिकारी के अथक प्रयासों और काउंसिलिंग का असर यह हुआ कि बेटे और बहू को अपनी गलती का अहसास हो गया। पुत्र ने अदालत के सामने माता-पिता से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और भविष्य में कभी परेशान न करने का वचन दिया।

समझौते (सुलहनामा) की मुय शर्तें

सुलह अधिकारी की देखरेख में दोनों पक्षों के बीच एक लिखित समझौता तैयार हुआ, जिसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं

सम्मान और देखरेखः- विपक्षी (बेटा-बहू) वादी (माता-पिता) का पूरा ध्यान रखेंगे, बीमारी में उचित इलाज कराएंगे और उनका पूरा सम्मान करेंगे।मकान पर कोई अवैध कब्जा नहीं- पुत्र ने स्पष्ट किया कि उनका मकान पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है और वे पूर्व की भांति केवल रहने के लिए मकान में रहेंगे।भविष्य की सुरक्षा- हालांकि आवेदक बुजुर्ग को अपने बच्चों से कोई भरण-पोषण (पैसा) नहीं चाहिए, लेकिन यदि भविष्य में समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो विपक्षियों के खिलाफ तत्काल कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बुजुर्ग बोले– कानून ने दी नई जिंदगी, हमारे बीच की गलतफहमियां हुईं दूर

सफलतापूर्वक हुए इस समझौते के बाद बुजुर्ग भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह 95 गज का मकान सोसाइटी के क्षेत्र से लिया था। उन्होंने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007' की सराहना करते हुए कहा–यह कानून हम जैसे असहाय बुजुर्गों के लिए एक वरदान है। सुलह अधिकारी डॉ. धीरेंद्र कुमार दोहरे के प्रयासों से हमारे और बच्चों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गईं और एक संतोषजनक सुलह हो सकी। हमें एसडीएम कोर्ट से इस आदेश की प्रमाणित कॉपी भी मिल गई है, जो भविष्य में हमारी सुरक्षा की गारंटी बनेगी।पुत्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कुछ गलतफहमियों के कारण विवाद हुआ था, जिसे अब सुलझा लिया गया है और वे अपने माता-पिता की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। यह मामला समाज के उन तमाम बुजुर्गों के लिए एक बड़ी मिसाल है, जो अपने ही बच्चों के अत्याचारों को भाग्य की लकीर मानकर चुपचाप सहते रहते हैं। 'वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007' न सिर्फ बुजुर्गों को त्वरित न्याय दिलाता है, बल्कि बिखरते हुए परिवारों को फिर से जोड़ने का काम भी करता है। जरूरत सिर्फ सही समय पर सही मंच तक आवाज पहुँचाने की है।

अगले हफ्ते (अंक- 3) ज़रूर पढ़ें: शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करें? साथ ही अगली नई सच्ची कहानी के साथ जानिए अगले हफ्ते केवल बीपीएस न्यूज़ पर। मदद के लिए यहाँ संपर्क करें: राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (Elderline) 14567 (टोल-फ्री नंबर)

नज़दीकी सहायताः- अपने क्षेत्र के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) कार्यालय या स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

बीपीएस न्यूज (साप्ताहिक समाचार पत्र)

मुद्रक प्रकाशक स्वात्वाधिकारी बुद्ध प्रकाश साहू द्वारा मां प्रिन्टर्स गार्डेन नं. 6-ए/7 रेल बाजार कानपुर नगर से मुद्रित एवं 344- बगाही भट्ठा टी.पी. नगर कानपुर से प्रकाशित। आर.एन.आई. नं. UPHIN/2016/66740, डाक पंजीयन सं. कानपुर सिटी 304/2024-2026, संपादक बुद्ध प्रकाश साहू मो.: 8423454502, व्हाट्सअप 9335908846
email:bps.knp786@gmail.com, info@bpsnews.in , www.bpsnews.in नोट-समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कानपुर नगर न्यायालय होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त लेखों एवं समाचारों की जिम्मेदारी लेखकों व संवाददाताओ की होगी। कृपया कोई भी आपत्ति हो तो 15 दिनो के अंदर भेजे।